

पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र में कमजोर वर्ग के लिये आवास तय समय में पूरे हों

मीडिया ऑडीटर, भोपाल (एजेंसी)। नगरीय प्रशासन विकास आयुक्त श्री संकेत भोंडवे ने सोमवार को धार जिले के पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र में निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने क्षेत्र में कमजोर वर्ग के व्यक्तियों के लिये बनाये जा रहे प्रधानमंत्री आवास योजना के आवासों की जानकारी ली। आयुक्त ने बैठक में क्षेत्र में निर्माणाधीन विकास कार्यों की समीक्षा भी की। आयुक्त ने कहा कि संजय जलाशय विकास कार्य के लिये अनुभवी योजनाकार से विस्तृत कार्य योजना बनवायी जाये। योजना में सिटी और बैन्को फरिस्ट, हेलीपेड, योगा जानकारी देने की समीक्षा भी की। आयुक्त ने कहा कि संजय जलाशय विकास कार्य के लिये अनुभवी योजनाकार से विस्तृत कार्य योजना बनवायी जाये। योजना में सिटी और बैन्को फरिस्ट, हेलीपेड, योगा जानकारी देने की समीक्षा भी की। आयुक्त ने कहा कि संजय जलाशय विकास कार्य के लिये अनुभवी योजनाकार से विस्तृत कार्य योजना बनवायी जाये। योजना में सिटी और बैन्को फरिस्ट, हेलीपेड, योगा जानकारी देने की समीक्षा भी की। आयुक्त ने कहा कि संजय जलाशय विकास कार्य के लिये अनुभवी योजनाकार से विस्तृत कार्य योजना बनवायी जाये। योजना में सिटी और बैन्को फरिस्ट, हेलीपेड, योगा जानकारी देने की समीक्षा भी की।

सामाजिक-आर्थिक स्थिति एक, फिर भी जातियों की श्रेणी में अंतर

मीडिया ऑडीटर, भोपाल (एजेंसी)। केंद्र सरकार के जातिगत जनगणना के ऐलान के बीच मध्य प्रदेश के कई जिलों में जातियों को लेकर गंभीर विसंगतियां सामने आई हैं। पिछले अंक में भास्कर ने बताया था कि मप्र की 32 जातियां ऐसी हैं, जिन्हें केंद्र सरकार ओबीसी नहीं मानती। गफलत यह भी है कि प्रदेश के एक ही जिले के अलग-अलग ब्लॉक में एक ही समाज को अलग-अलग वर्गों में गिना गया है। कहीं एससी तो कहीं ओबीसी। मप्र में 7 जातियों का का गणित 69 साल से उलझा है। इन जातियों की सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक स्थिति में फर्क नहीं है, फिर भी जिला और तहसील बदलने पर सरकारी रिकॉर्ड में इनके वर्ग व अधिकार बदल जाते हैं। उदाहरण- पारधी एससी, एसटी, जनरल तीनों में है। भोपाल, सीहोर व रायसेन जिले में तो इसे ओबीसी वर्ग में करने की सिफारिश भी हुई, लेकिन इस पर अब तक फैसला नहीं हो सका है। इसी तरह, प्रजापति समाज दतिया के दो ब्लॉक में एससी है जबकि एक में ओबीसी। इन विसंगतियों के चलते जाति जनगणना में गलत जानकारी दर्ज होने का खतरा बढ़ गया है। कुछ समाजों ने खुद को एससी-एसटी में शामिल कराने की मांग को लेकर आंदोलन शुरू कर दिए हैं।

राजाभोज एयरपोर्ट पर चेक-इन से पहले काटा केक

मीडिया ऑडीटर, भोपाल (एजेंसी)। एअर इंडिया की भोपाल-मुंबई फ्लाइट के यात्रियों ने रविवार शाम राजाभोज एयरपोर्ट पहुंचकर चेक-इन से पहले केक काटा। एयरपोर्ट डायरेक्टर रामजी अवस्थी सहित स्टाफ के सदस्यों ने यात्रियों को सुविधाओं की जानकारी दी। 162 सीटर फ्लाइट में भोपाल से मुंबई के लिए 161 यात्री रवाना हुए। वहीं मुंबई से भोपाल के लिए 160 यात्री भोपाल पहुंचे। यहां पहुंचने पर फ्लाइट को वाटर केनन सेल्यूट ?दिया गया।

परीक्षा फॉर्म फॉरवर्ड नहीं करने पर लगाए थे बैड टच के आरोप



मीडिया ऑडीटर, भोपाल (एजेंसी)। निजी कॉलेज के डायरेक्टर पर बैड टच का आरोप लगाने वाली चार छात्राओं में से तीन ने अपने बयान पुलिस में दर्ज कराए हैं। उनका कहना है कि छेड़छाड़ के आरोप उन्होंने एग्जाम फॉर्म फॉरवर्ड नहीं होने के कारण लगाए थे। चौथी छात्रा अपने बयान दर्ज कराने नहीं पहुंची।

इधर, डायरेक्टर ने भी 18 से 22 मई तक के सीसीटीवी फुटेज पुलिस को उपलब्ध कराए हैं। छात्राओं द्वारा जिन तारीखों की घटना बताई गई है, उन दिनों

डायरेक्टर ज्यादातर समय मीटिंग और एसडीएम कार्यालय में व्यस्त थे। पुलिस की जांच में सामने आया है कि अटेंडेंस शॉर्ट होने के कारण छात्रों के एग्जाम फॉर्म फॉरवर्ड नहीं हो रहे थे। छात्राएं कॉलेज प्रबंधन द्वारा एग्जाम फॉर्म फॉरवर्ड नहीं किए जाने की शिकायत लेकर बरकतउल्ला यूनिवर्सिटी भी पहुंची थीं।

बीयू के एक अफसर ने डायरेक्टर अरुण पांडेय को एग्जाम फॉर्म फॉरवर्ड करने की सिफारिश की। उन्होंने बताया था कि फॉर्म फॉरवर्ड करने का अधिकार उनके पास नहीं है। इसी दिन चारों छात्राएं कॉलेज के एक पूर्व छात्र के साथ पिपलानी थाने पहुंचीं और डायरेक्टर के खिलाफ बैड टच की शिकायत कर दी। पूर्व छात्र 2024 में कॉलेज से बीएएलएलबी करके पासआउट हो चुका है। उसने दो महीने पहले डायरेक्टर के खिलाफ शिकायत की थी। पुलिस ने जांच को नस्तीबद्ध कर दिया था। पुलिस डायरेक्टर के बयान दर्ज कर चुकी है।

रोज 50 हजार की आबादी परेशान, मेट्रो तो चली नहीं, 7 साल से रुला रही इसके रूट की सड़के

मीडिया ऑडीटर, भोपाल (एजेंसी)। शहर में 2018 से मेट्रो के प्रायोरिटी कॉरिडोर पर काम चल रहा है। सुभाष नगर से एम्स तक 6.22 किमी रूट पर मेट्रो का संचालन कब शुरू होगा, ये आज भी कहना मुश्किल है। लेकिन इसकी वजह से पिछले सात साल से इस पूरे इलाके में सड़कें बदहाल हैं। एमपी नगर, आरकेएमपी और अरेरा हिल्स आने-जाने वाले करीब 50 हजार लोग रोज ये परेशानी झेल रहे हैं। मानसून आने को है। हलकी बारिश में ही सड़क पर कीचड़, जलभराव और उसके कारण ट्रैफिक जाम जैसी समस्याएं हो सकती हैं। नियम कहता है, मेट्रो प्रोजेक्ट के दौरान ट्रैफिक की समस्या न हो, इसकी व्यवस्था करने की जिम्मेदारी मेट्रो रेल कंपनी की है। रूट डाइवर्ट करना और जिस रूट पर ट्रैफिक चल रहा है, उसे मोटरबल बनाना भी कंपनी की ही जिम्मेदारी है। सुभाष नगर मेट्रो स्टेशन से आरबीआई तक 1.6 किमी की सड़क में 400 मीटर रास्ता खराब है। मेट्रो स्टेशन के नीचे 100 मी. रास्ते में गड्?ढे और मिट्टी हैं। बारिश में यह हिस्सा बेहद फिसलन भरा हो जाता है। मैदा मिल के पास रोड ऊबड़-खाबड़ हो गई है।



आयकर कार्यालय के सामने की सड़क भी खराब हो चुकी है। आरबीआई के सामने की सड़क तो ठीक है। लेकिन किनारे पर डिवाइडर के तौर पर ड्रम और रस्सी बांधी है, जो कई बार टूट जाती है जिस कारण गाड़ियां कट समझ कर सड़क से नीचे उतर सकती हैं। रात में ये रस्सियां नजर न आने से दुर्घटनाओं का खतरा रहता है। साकेत नगर से अलकापुरी स्टॉप = एक तरफ

की सड़क ही बंद... साकेत नगर से अलकापुरी बस स्टॉप तक 1 किमी का रास्ता खराब है। सिर्फ एक तरफ की सड़क आने-जाने के लिए चल रही है। दूसरी सड़क पूरी तरह खराब हो चुकी है। कहीं बड़े पत्थर तो कहीं मिट्टी के टीले होने के कारण सड़क बंद पड़ी है। अलकापुरी स्टॉप से बीएसएसएस कॉलेज = 700 मीटर सड़क खराब... अलकापुरी बस स्टॉप

एयरक्राफ्ट पार्किंग की संख्या 13 से 20 होगी

मीडिया ऑडीटर, भोपाल (एजेंसी)। राजा भोज एयरपोर्ट पर जल्द ही 850 सीटर एयरबस ए-380 की भी लैंडिंग हो सकेगी। अभी 850 सीटर एयर बस लैंड करने के लिए एयरपोर्ट पर रनवे की लंबाई पर्याप्त नहीं है। इसी को देखते हुए एयरपोर्ट प्रबंधन अब रनवे की लंबाई को 9000 से बढ़ाकर 11000 फीट करने जा रहा है।

रनवे की लंबाई बढ़ाने के बाद इंटरनेशनल फ्लाइट के रूप में संचालित किए जाने वाले बड़े बोइंग को भी यहां पर लैंड किया जा सकेगा। शनिवार को एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष विपिन कुमार ने पीएम मोदी के सामने मप्र के एयरपोर्ट्स को लेकर प्रेजेंटेशन दिया था। इससे पहले एयरपोर्ट डायरेक्टर रामजी अवस्थी ने उन्हें बताया कि राजधानी के एयरपोर्ट का रनवे 9000 फीट ही है। चूंकि, यहां इंटरनेशनल फ्लाइट शुरू होने की उम्मीद बड़ी है, ऐसे में बोइंग और बड़े आकार वाली एयर बस की लैंडिंग के लिए रनवे की लंबाई कम से कम 11000 फीट होना चाहिए। एयरपोर्ट डायरेक्टर ने एयरपोर्ट अथॉरिटी के अध्यक्ष को लंबाई बढ़ाने का प्रस्ताव दिया, जिसे तत्काल सहमति भी मिल गई।

एयरपोर्ट डायरेक्टर ने बताया कि जल्द ही



इसका प्रस्ताव एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को भेजा जाएगा। वहां से बजट रिलीज होने सहित आगे की प्रक्रिया शुरू होगी। अभी भोपाल एयरपोर्ट पर 250 सीटर से अधिक के एयरक्राफ्ट की लैंडिंग की जा सकती है।

एयरपोर्ट पर फिकायती रेड आई फ्लाइट सहित अन्य फ्लाइट्स के लिए एप्रॉन (एयरक्राफ्ट की पार्किंग) की संख्या 13 से बढ़ाकर 20 की जाएगी। इसकी मंजूरी भी मिल गई है। एयरपोर्ट के अधिकारियों के मुताबिक आए दिन यहां आवागमन करने वाले विभिन्न एयरक्राफ्ट के लिए यहां मौजूद पार्किंग कम पड़ती है। इसी को देखीं हुए अथॉरिटी ने इनकी संख्या 13 से बढ़ाकर 20 करने पर सहमति दी है।

नौका पर श्याम-राधा की लीला देख मंत्रमुग्ध हुए श्रद्धालु

मीडिया ऑडीटर, भोपाल (एजेंसी)। कमला पार्क स्थित शीतल दास की बगिया में इस समय भक्ति का महासागर उमड़ पड़ा है। श्याम ताली संकीर्तन परिवार द्वारा आयोजित श्याम अलबेला नौका विहार महोत्सव में श्रद्धालुओं की भीड़ जुहारी

दीपों से सजाया गया है, जो श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। शाम 7 बजे जैसे



बड़ी झील के मध्य नौका पर जब श्री श्याम और राधारानी की रासलीला शुरू हुई, तो पूरा वातावरण वृंदावन में बदल गया। झील पर तैरती नौका और उस पर सजी रासलीला ने श्रद्धालुओं को भक्ति और भावनाओं में डुबो दिया है। हर तरफ श्याम नाम की गुंज है, दीपों की जगमगाहट है, और भक्तों की आंखों में आस्था की चमक। कार्यक्रम में श्रेष्ठ दीक्षित (कानपुर) और साक्षी चोपड़ा (दिल्ली) की भजन प्रस्तुतियां चल रही हैं। श्रोताओं की तालियों और श्याम बाबा की जय के उद्घोष से माहौल भक्तिमय हो गया है। बाबा श्याम का कोलकाता से मंगाए गए फूलों से श्रृंगार किया गया। श्रद्धालुओं ने छप्पन भोग के दर्शन किए और आरती में भाग लिया। आयोजन स्थल को फूलों, रंग-बिरंगी लाइटों और

ही कार्यक्रम शुरू हुआ, कमला पार्क के आसपास श्रद्धालुओं का तांता लग गया। हजारों की संख्या में लोग अब भी आयोजन स्थल पर पहुंच रहे हैं। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक, हर आयु वर्ग के लोग इस अलौकिक रासलीला का आनंद ले रहे हैं। आयोजन समिति के अनुसार, महोत्सव की प्रेरणा करने वाले श्याम, कराने वाले श्याम की भावना से जुड़ी है और यह आयोजन पूर्णतः सेवा भाव से समर्पित है।

पूर्व मुयमंत्री स्व. श्री बाबूलाल गौर की जयंती पर कार्यक्रम

मीडिया ऑडीटर, भोपाल (एजेंसी)। बाबूलाल गौर शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय भेल भोपाल में सोमवार को मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्व. श्री बाबूलाल गौर की जयंती पर पिछड़ वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण, घुमंतु एवं अर्धद घुमंतु कल्याण राज्यमंत्री श्रीमती कृष्णा गौर ने स्व. बाबूलाल गौर की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। राज्यमंत्री श्रीमती गौर ने कहा कि आज का दिन राजनीति के क्षेत्र में सादगी और शुचित्वा के प्रतीक विनम्र, सहज और सरल व्यक्तित्व के धनी, आदर्श के केन्द्र बाबूजी पूर्व मुख्यमंत्री स्व. श्री बाबूलाल गौर के आदर्शों पर चलने का संकल्प का दिन है। मैं उनकी ऐसी बेटी हूँ, जिसका मार्गदर्शन उन्होंने पल-पल पर किया। श्री गौर सच्चे जनसेवक और कर्मयोगी थे।

राज्यमंत्री श्रीमती गौर ने कहा कि महाविद्यालय में वर्तमान सत्र 2025-26 से पाठ्यक्रम, बी.ए. यूईएम सत्र हॉस्पिटलिटी ऑपरेशंस प्रारंभ हो रहा है। इसमें प्रवेशित विद्यार्थी को तृतीय वर्ष में को 8,000 रुपये



प्रतिमाह सत्यपेंड की पात्रता होगी। उन्होंने उच्च शिक्षा विभाग से महाविद्यालय परिसर में स्वीकृत मल्टीपर्पज हॉल के लिये 3 करोड़ 65 लाख रुपये की। आर्वाटिन राशि को बख़्कर 10 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित किये जाने की अनुशंसा की है। श्रीमती गौर ने बाबूलाल गौर शोध समन्वय प्रकोष्ठ का उद्घाटन भी किया। इस शोध प्रकोष्ठ में शोध प्रबंध और श्री बाबूलाल गौर के जीवन पर आधारित

बहुमूल्य साहित्य उपलब्ध है। इसी के साथ राज्यमंत्री श्रीमती गौर ने महाविद्यालय में 21 लाख रुपये की राशि से नवनिर्मित कार पार्किंग शेड का लोकार्पण किया। उन्होंने महाविद्यालय परिसर में वृक्षारोपण में भी किया। कार्यक्रम का संचालन महाविद्यालय के जनभागीदारी समिति अध्यक्ष श्री बाबूलाल अहिरवार ने किया। प्राचार्य डॉ. संजय जैन ने बताया कि महाविद्यालय में श्री बाबूलाल गौर शोध समन्वय प्रकोष्ठ संचालित किया जा रहा है, जिसके माध्यम से राजनीति एवं समाज विज्ञान विद्यार्थी श्री गौर के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर पीएच.डी. कर सकते हैं। इस अवसर पर गोविन्दपुरी क्षेत्र के विभिन्न पार्षदाण, वरिष्ठ समाजसेवी, वरिष्ठ कार्यकर्ताओं, महाविद्यालय के प्राध्यापकगण एवं विद्यार्थियों ने बाबूजी की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित किये। इस अवसर पर नोबल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एवं कांठियंक सेंटर भोपाल तथा श्री सई वेलनेस फिट जोन भोपाल द्वारा लगाये गये शि्विर में कई लोगों ने अपने स्वास्थ्य का परीक्षण भी कराया।

मध्यप्रदेश सरकार का प्रण - सुरक्षित भविष्य के लिए जल संवर्धन और संरक्षण

मीडिया ऑडीटर, भोपाल (एजेंसी)। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के जल संरक्षण-संवर्धन के संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने जल गंगा संवर्धन अभियान का शुभारंभ 30 मार्च को किया था। पूरे प्रदेश में अभियान प्रारंभ से ही जन-आंदोलन बनकर आगे बढ़ा और उसके परिणाम भी सामने आने लगे हैं। पहली बारिश में ही अभियान में बनाए गए खेत तालाब लबालब हो गए। केंद्र सरकार के जल शक्ति मंत्रालय के जल संचय, जनभागीदारी अभियान में जल संचय के लिए खंडवा जिले को देश में प्रथम स्थान मिला है और राज्यों की श्रेणी में मध्यप्रदेश चौथे स्थान पर रहा है। खेत तालाबों में हो रहे जल संचय से किसानों को आवश्यकता के समय पर्याप्त जल उपलब्ध रहेगा, भूजल स्तर में वृद्धि होगी और खेत में मौसमी फसलों के साथ ही मछली पालन एवं तालाब के किनारों पर बागवानी का भी अवसर मिलेगा। वारा सिवनी में तुमाड़ी की श्रीमती सुनीता जैराम के खेत-

तालाब बनाया था। करीब 6 फिट गहराई में बने खेत तालाब से सुनीता और उनके पति मिलकर मछली पालन के साथ ही खरीफ में गेहूं और रबी में धान की फसल ले रहे हैं। इससे उन्हें 1 लाख रुपये तक का मुनाफा हो रहा है। बन रहे नये खेत तालाब, पुराने कुओं, बावड़ियों और तालाबों का हो रहा जीर्णोद्धार

शहडोल जिले में आगामी तीन माह तक जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत नये तालाब बनाये जा रहे हैं, साथ ही तालाबों, बावड़ियों और कुंओं का जीर्णोद्धार भी किया जा रहा है। नदियों को साफ-स्वच्छ एवं प्रवाहमान बनाए रखने के लिए भी कार्य किए जा रहे हैं। अभियान के अंतर्गत जनपद पंचायत गोहपारू के ग्राम पंचायत पोड़ी, नवागांव, हर्ही में नवीन खेत तालाब बनाए गए। जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत कटनी शहर की कटनी नदी के कटाए घाट में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जलकुंभी की सफाई का अभियान चलाया गया।

कंपनी द्वारा नवीन कनेक्शन बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के जारी किये जा रहे हैं। उपभोक्ताओं को नवीन कनेक्शन के लिये मात्र दो दस्तावेज क्रमशः आवेदक का पहचान पत्र एवं परिसर के स्वामित्व या अधिवास संबंधी साक्ष्य ऑनलाइन अपलोड करना आवश्यक होता है। माननीय विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित शुल्क का ऑनलाइन भुगतान प्राप्त होने तथा तकनीकी रूप से साध्य पाये जाने पर, तय समय-सीमा यथा कमिश्नरी मुख्यालय में 5 दिवस, अन्य शहरी क्षेत्र में 7 दिवस तथा ग्रामीण क्षेत्र में 15 दिवस के भीतर निर्बाध रूप से विद्युत कनेक्शन समस्त कंपनी क्षेत्र में प्रदाय किये जा रहे हैं।



उपलब्ध कराये जा रहे हैं। इस सुविधा से एक ओर जहाँ उपभोक्ताओं को आसानी से बिजली कनेक्शन मिल रहे हैं वहीं दूसरी ओर इस ऑनलाइन प्रक्रिया से उपभोक्ताओं और बिजली कंपनी के समय और संसाधनों की भी बचत हो रही

है। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने बताया है कि उपभोक्ताओं को नवीन विद्युत कनेक्शन प्रदान किये जाने के लिये कंपनी की अत्यंत पारदर्शी ऑनलाइन प्रक्रिया कंपनी के सरल संयोजन पोर्टल पर उपलब्ध है। इसके माध्यम से

जनसुनवाई में कलेक्टर ने सुनी 173 आवेदकों की समस्याएं



मीडिया ऑडीटर, सीधी (निप्र)। नागरिकों के समस्याओं के त्वरित निराकरण के लिये शासन के निर्देशानुसार प्रत्येक मंगलवार को जिला पंचायत सभागार में सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक जनसुनवाई आयोजित की जाती है। इस बार आयोजित जनसुनवाई में कलेक्टर स्वरोचिष सोमवंशी द्वारा जिले के विभिन्न अंचलों से आए 173 आवेदकों की समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुनते हुए संबंधित अधिकारियों से संपर्क कर शिकायत को वस्तुस्थिति की जानकारी प्राप्त की गई तथा उसके निराकरण के लिए निर्देश दिए गए। अनिराकृत आवेदनों के लिये समय-सीमा निर्धारित कर अधिकारियों को

समय-सीमा में निराकरण करने के निर्देश दिए गए हैं। जनसुनवाई में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत अंशुमन राज, उपखण्ड अधिकारी गोपद बनास नीलेश शर्मा, संयुक्त कलेक्टर एसपी मिश्रा, अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी धनंजय मिश्रा सहित सभी विभागों के जिला अधिकारी उपस्थित रहे। आज आयोजित जनसुनवाई में समस्त उपखण्ड अधिकारी, तहसीलदार और मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत भी वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जिला स्तरीय जनसुनवाई से जुड़े रहे।

मैहर में एनडीआरएफ टीम ने एनजीओ और स्टाफ को दिया आपदा प्रबंधन का प्रशिक्षण



मीडिया ऑडीटर, सतना (निप्र)। आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन योजना के तहत 11 वीं वाहिनी राष्ट्रीय आपदा मोचन बल तथा जिला के दिशा-निर्देशन में 2 जून 2025 को 11 वाहिनी एनडीआरएफ वाराणसी की प्रशिक्षित एवं अनुभवी टीम द्वारा नगर पालिका भवन में क्षमता निर्माण कार्यक्रम के तहत

एनजीओ एवं नगरपालिका स्टाफ को आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबंधन का प्रशिक्षण दिया गया। टीम ने भूकम्प से बचाव, सड़क सुरक्षा, बाढ़ में बचाव के तरीके, बाढ़ की स्थिति में क्या करें और क्या न करें, सीपीआर देने की विधि, गले में पसी बाहरी वस्तु के निकालने के तरीके, शारीरिक चोटों में रक्तस्त्राव



मीडिया ऑडीटर, सीधी (निप्र)। सीधी जिले में विकसित कृषि संकल्प अभियान के अंतर्गत कृषि विज्ञान केंद्र सीधी एवं कृषि अधिकारियों द्वारा किसानों को नरवाई नहीं जलाने तथा उससे जैविक खाद बनाने की सलाह दी गई। उन्होंने बताया कि नरवाई जलाने से एक ओर जहां खेतों में अग्नि दुर्घटना की आशंका रहती है। वहीं मिट्टी की उर्वरकता पर भी विपरीत असर पाता है। इसके साथ ही धूरें से कार्बन डायऑक्साइड की मात्रा वातावरण में जाती है जिससे वायु प्रदूषण होता है। मिट्टी की उर्वरा शक्ति लगभग 6 इंच की ऊपरी सतह पर ही होती है। इसमें खेती के लिए लाभदायक मित्र जीवाणु उपस्थित

विकसित कृषि संकल्प अभियान में छठवें दिन पहले दल द्वारा रामपुर नैकिन विकासखंड में कपुरी, भरतपुर, बड़गौना, दूसरे दल द्वारा सिहावल विकासखंड में सिहावल, महुआर, सेमरी तथा तीसरे दल द्वारा कुसमी विकासखंड में गुडुआधर, खोखरा एवं अमगांव में किसान संगोष्ठी का आयोजन किया



रहते हैं। नरवाई जलाने से यह नष्ट हो जाते हैं, जिससे भूमि की उर्वरा शक्ति को नुकसान होता है। नरवाई जलाने की बजाए यदि फसल अवशेषों को एकत्रित करके जैविक खाद बनाने में उपयोग किये तो यह बहुत लाभदायक होगा। नाडेप तथा वर्मीविधि से नरवाई से जैविक खाद आसानी से बनाई जा सकती है। इस खाद में फसलों के लिए पर्याप्त पोषक तत्व रहते हैं। उन्होंने बताया कि इसके आलावा खेत में रोटोवेटर अथवा डिस्क हैरो चलाकर भी फसल के बचे हुए भाग को मिट्टी में मिला देने से मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार होता है। गेहूं की फसल के बाद नरवाई को

खाद में बदलने तथा बिना जुताई किए फसलों की बुआई के लिए सुपर सीडर तथा हैप्पी सीडर का उपयोग बहुत लाभकारी है। इससे नरवाई नष्ट होने के साथ जुताई और बुवाई का खर्च और समय दोनों बचेगा। साथ ही नरवाई से खाद भी बन जाएगी। विकसित कृषि संकल्प अभियान के अन्तर्गत बुधवार को पहले दल द्वारा रामपुर नैकिन विकासखंड में बघवार, नैकिन, अगडाल, दूसरे दल द्वारा सिहावल विकासखंड में लोआ, पतुलखी, बहरी एवं तीसरे दल द्वारा कुसमी विकासखंड में पोंडी, लुरघुटी तथा ददरी में कार्यक्रम का आयोजन किया जायेगा।

बैंक सखी बनकर पुष्पा ने बदली अपनी किस्मत



मीडिया ऑडीटर, मैहर (निप्र)। मैहर जिले के विकासखण्ड अमरपाटन की ग्राम पंचायत धोबहट में रहने वाली 32 वर्षीय पुष्पा साकेत के परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होने के कारण वह हमेशा कुछ ऐसा करने की सोचती रहती, जिससे परिवार का खर्च चल सके। लेकिन आर्थिक तंगी की वजह से उनका यह सपना पूरा होता नहीं दिख रहा था। तभी पुष्पा साकेत को शारदा स्व सहायता समूह से जुड़कर वह आजिविका मिशन द्वारा उन्हें बैंक सखी बनने का मौका मिला। बैंक सखी के रूप में लोगों से

जुड़ने के बाद पुष्पा का आत्मविश्वास बढ़ा और वह अन्य कामों के लिए आगे बढ़ने लगी। अब पुष्पा अपने नये कौशल से लैस अपने गांव में घर-घर जाकर लोगों को बचत खातों के लाभों के बारे में जानकारी दे रही है। साथ ही पुष्पा ने ऋण आवेदनों में सहायता करना और महिलाओं के लिए वित्तीय सेवाओं तक आसान पहुंच की सुविधा शुरू कर दिया है। इस व्यवसाय से पुष्पा अब हर महीने 10 हजार रुपये कमा रही है। बैंक सखी के माध्यम से पुष्पा 105 स्व-सहायता समूह एवं 9240 हितग्राहियों का बीमा भी कर चुकी है।

जमोड़ी में श्रमिकों के लिए विधिक साक्षरता शिविर आयोजित

मीडिया ऑडीटर, सीधी (निप्र)।

मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सीधी के अध्यक्ष श्री प्रयाग लाल दिनकर के मार्गदर्शन में मंगलवार दिनांक 03.06.2025 को ग्राम जमोड़ी में श्री मनीष कौशिक जिला विधिक सहायता अधिकारी के द्वारा (नालसा असंगठित क्षेत्र के कामगारों/श्रमिकों के लिए विधिक सेवाएं योजना) अंतर्गत विधिक जागरूकता एवं साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। उक्त शिविर में श्री कौशिक द्वारा गैर संगठित क्षेत्र के मजदूरों के सशक्तिकरण एवं श्रमिकों के कानूनी अधिकार, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को विधिक सेवाएं, नालसा (नशा पीड़ितों को विधिक सेवाएं एवं नशा उन्मूलन के लिए विधिक सेवाएं) योजना, 2015, आदिवासियों को



विधिक सेवाएं, नालसा (गरीबी उन्मूलन योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन के लिए विधिक साक्षरता शिविर), जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा श्रमिकों के लिए संचालित योजनाओं तथा श्रमिकों हेतु शासन द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी दी गई। शिविर में चीफलीगल एड डिफेंस काउंसिल श्री देवेन्द्र प्रसाद मिश्रा ने नालसा एसिड अटैक पीड़ितों के लिए

विधिक सहायता योजना, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए विधिक सेवा योजना, वरिष्ठ नागरिकों को विधिक सहायता एवं शासन की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। उक्त शिविर में जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री मनीष कौशिक चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल श्री देवेन्द्र प्रसाद मिश्रा एवं आमजन उपस्थित रहे।

नशा मुक्ति अंतर्गत विधिक जागरूकता शिविर का किया गया आयोजन

मीडिया ऑडीटर, सीधी (निप्र)।

मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सीधी के अध्यक्ष श्री प्रयाग लाल दिनकर के मार्गदर्शन में जिला विधिक सहायता अधिकारी सीधी श्री मनीष कौशिक द्वारा मंगलवार दिनांक 03.06.2025 को जिला चिकित्सालय सीधी में नालसा नशा पीड़ितों को विधिक सेवाएं एवं नशा उन्मूलन के लिए विधिक सेवाएं योजना 2015 अंतर्गत विधिक जागरूकता एवं साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया।

शिविर में जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री मनीष कौशिक द्वारा नालसा नशा पीड़ितों को विधिक सेवाएं एवं नशा उन्मूलन के लिए विधिक सेवाएं योजना 2015, नालसा एसिड हमले के पीड़ितों के लिए विधिक सेवाएं योजना 2015 की जानकारी दी गई। साथ ही राष्ट्रीय



विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली द्वारा हेल्पलाइन नंबर 15100 के बारे में विस्तार से बताया।

चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल श्री देवेन्द्र प्रसाद मिश्रा ने उपस्थित आमजन को बताया कि बच्चों और युवाओं पर नशे का गलत असर पड़ता है, छोटी उम्र में ही नशा

करने के शारीरिक विकास के साथ-साथ मानसिक विकास तक रूक जाता है। उक्त शिविर में जिला विधिक सहायता अधिकारी सीधी श्री मनीष कौशिक एवं चीफलीगल एड डिफेंस काउंसिल श्री देवेन्द्र प्रसाद मिश्रा एवं आमजन उपस्थित रहे।

विष्व पर्यावरण दिवस पर 5 जून को होंगी ग्राम सभायें

मीडिया ऑडीटर, सतना (निप्र)। कलेक्टर डॉ. सतीश कुमार एस ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर 5 जून को जिले में ग्राम सभाओं का आयोजन करने के निर्देश दिये हैं। मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम सभा अधिनियम 1993 की धारा 6 और मध्यप्रदेश ग्रामसभा (सम्मिलन की प्रक्रिया) नियम 2001 के अंतर्गत आयोजित होने वाले ग्रामसभा में सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तीकरण, स्वास्थ्य विभाग, महिला एवं बाल विकास, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, मध्यप्रदेश राज ग्रामीण आजीविका मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण से संबंधित एजेंडा बिन्दु चर्चा के लिए शामिल किये गये हैं।

मैहर जिले की डीएलसीसी की त्रैमासिक बैठक संपन्न

मीडिया ऑडीटर, मैहर (निप्र)। मैहर जिले की जिला स्तरीय बैंकर्स समिति की त्रैमासिक बैठक कलेक्टर रानी बाटड की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में भारतीय रिजर्व बैंक से नवनीत तिवारी, नाबाई से जीडी गोपेश, अग्रणी जिला प्रबंधक गोतम शर्मा सहित मैहर के सभी बैंकों के शाखा प्रबंधक एवं शासकीय विभागों से विभिन्न अधिकारीगण उपस्थित रहे। बैठक में बताया गया कि विगत तिमाही बैठक में मैहर जिले का जमा ऋण अनुपात 68 प्रतिशत रहा। जिस पर कलेक्टर द्वारा निर्देशित किया गया कि जमा ऋण अनुपात अगली तिमाही तक 70 प्रतिशत करने का प्रयास करें। बैंक ऑफ़इंडिया, भारतीय स्टेट बैंक एवं यूको बैंक का जमा ऋण अनुपात कम



रहने पर कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए। भारतीय रिजर्व बैंक के अधिकारी द्वारा बताया गया कि मध्यप्रदेश का कुल जमा ऋण अनुपात 82 प्रतिशत है। अग्रणी जिला प्रबंधक द्वारा बताया गया कि रीवा संभाग में सबसे अधिक जमा ऋण अनुपात मैहर जिले का है एवं

सबसे कम अनुपात सिंगरौली जिले का है। मैहर जिले में बैंक शाखाओं के जल्दतर से कम होने पर कलेक्टर द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त की गई एवं सभी बैंकों एवं राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति को पत्र लिखने के लिए निर्देश दिये। इसके साथ ही आदिवासी वित्त की योजनाएं जैसे टंट्या मामा एवं

बिरसा मुंडा में कम प्रगति को लेकर अप्रसन्नता व्यक्त की गई एवं आगामी वर्ष में लक्ष्य पूर्ण करने के निर्देश दिए गए।

अंत्यावसायी विभाग, एनआरएलएम, पशुपालन एवं केसीसी की विभिन्न योजनाओं में लक्ष्य के सापेक्ष संतोषजनक प्रगति पर संतोष व्यक्त किया गया। साथ ही कलेक्टर द्वारा एनआरएलएम को विभिन्न ग्रामों में पर्याप्त प्रकरण के निर्देश दिए गए।

सीएम हेल्पलाइन में वित्त विभाग की प्रगति संतोषजनक पाई गई। अग्रणी जिला प्रबंधक द्वारा बताया गया कि प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना आगामी समाधान ऑनलाइन में चयनित विषय है, अतः इससे संबंधित शिकायतों में सावधानी बरते। पीएम स्वनिधि योजना के शेष प्रकरणों की समीक्षा भी की गई। इस

अवसर पर जिला विकास प्रबंधक नाबाई जीडी गोपेश द्वारा संभवतः ऋण योजना पर जानकारी दी गई।

बैठक के अंत में अग्रणी जिला प्रबंधक के द्वारा प्रधानमंत्री सूर्यहर योजना एवं स्वास्मिन्त योजना के बारे में बैंकर्स को जानकारी दी गई। बैंकर्स द्वारा आगामी वर्ष में लक्ष्यपूर्ति के आश्वासन के साथ बैठक संपन्न हुई।

वार्षिक ऋण योजना 2025-26 का विमोचन कलेक्टर रानी बाटड द्वारा मैहर जिले की वार्षिक ऋण योजना 2025-26 का विमोचन किया गया। अग्रणी जिला प्रबंधक गोतम शर्मा द्वारा जानकारी दी गई कि इस बार मैहर जिले के लक्ष्य ब्याँकवार एवं शाखा वार वितरित किए गए हैं।

विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत ड्रोन का प्रदर्शन



मीडिया ऑडीटर, सतना (निप्र)। विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत मंगलवार को रामपुर बघेलान विकासखण्ड अंतर्गत ग्राम पंचायत तिहाई में कृषकों के समक्ष ड्रोन द्वारा खेत में दवा के छिड़काव का प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर कृषक संगोष्ठी का कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। जिसमें कृषि वैज्ञानिक, उपसंचालक पशुपालन, कृषि, उद्यान, फसल बीमा के अधिकारियों द्वारा अपने-अपने विभाग की योजनाओं की जानकारी कृषकों को दी गई। इस दौरान किसानों को मिट्टी नमूना, नरवाई प्रबंधन से भी अवगत कराया गया।

कलेक्टर ने सुनी 149 आवेदकों की समस्यायें



मीडिया ऑडीटर, सतना (निप्र)। कलेक्टर डॉ. सतीश कुमार एस ने मंगलवार को होने वाली जनसुनवाई में जिले के दूर-दराज के क्षेत्रों से आये 149 आवेदकों से उनकी समस्यायें सुनी और अधिकारियों को तत्काल निराकरण के निर्देश दिये।

इस मौके पर अपर कलेक्टर स्वर्णिल वानखडे, एसडीएम एलआर जांगडे सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। जनसुनवाई में जमीन का सीमांकन कराने, अनुकंपा नियुक्ति, खाद्यान्न पात्रता पर्ची, दाखिल-खारिज कराने, प्रधानमंत्री आवास योजना, कलेक्टर रानी बाटड ने मंगलवार को जनसुनवाई में जिले के विभिन्न अंचलों से प्राप्त 42 आवेदनों पर सुनवाई करते हुए संबंधित अधिकारी को निराकरण करने के निर्देश दिए। इस मौके पर विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

श्रमायुक्त द्वारा किया गया प्रिज्म जॉनसन फैक्ट्री का निरीक्षण



मीडिया ऑडीटर, सतना (निप्र)। श्रमायुक्त श्रीमती रजनी सिंह द्वारा मंगलवार को रामपुर बघेलान क्षेत्र अंतर्गत मनकहरी में स्थित प्रिज्म जॉनसन प्राइवेट लिमिटेड फैक्ट्री का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान फैक्ट्री के अंदर श्रमिकों एवं क्षेत्र की वाटर टेबल में सुधार मापदण्डों के आधार पर लगाये गए सुरक्षा उपकरणों, सुरक्षा ध्यान दिये जाने के लिए निर्देशित किया गया। इस दौरान श्रमायुक्त ने फैक्ट्री प्रबंधन से पौधा रोपण एवं क्षेत्र की वाटर टेबल में सुधार के लिए प्रयास किये जाने के लिए आग्रह किया गया। निरीक्षण के समय संचालक नमिता तिवारी, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा इन्डोर अनुराग प्रताप सिंह, प्रभारी सहायक श्रमायुक्त कार्यालय सतना, कारखाना प्रबंधक प्रिज्म जॉनसन उपस्थित रहे।

जिला चिकित्सालय में क्लबफुट से पीडित बच्चों का किया गया इलाज

मीडिया ऑडीटर, सतना (निप्र)। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सतना डॉ. एलके तिवारी ने बताया कि जिला चिकित्सालय में क्लब फुट से पीडित 16 बच्चों का पंजीयन किया गया। जिसमें अस्थि रोग विशेषज्ञ डॉ. शरद दुबे द्वारा क्लब फुट के 3 बच्चों का पोनसेटी विधि से इलाज किया गया तथा 6 बच्चों को सूज प्रदान किये गये तथा 7 बच्चों का प्लास्टर किया गया। बताया गया कि क्लब फुट एक जन्मजात विकृति बच्चों के जन्म के समय बच्चों में मौजूद एक संचारात्मक परिवर्तन है जो हृदय, मस्तिष्क, पैर जैसे शरीर के किसी भी हिस्से को प्रभावित कर सकते हैं। यह एक जन्मजात दोष है। जिसमें बच्चों के एक या दोनो पैर अंदर की ओर मुड़े हुये होते हैं। 1000 सहाजक बच्चों में से 2 बच्चों में यह दोष पाया जाता है, जिसका इलाज संभव है। जिसके बाद ये बच्चे अन्य बच्चों की तरह सभी गतिविधियां सामान्य रूप से कर सकते हैं। जिसमें अनुष्का फाउंडेशन द्वारा सहयोग प्रदान किया गया। शिविर में डीईआईएम डॉ. मीना द्विवेदी, डॉ. चन्द्रकांत द्विवेदी, डॉ. स्मिता सिंह, आर्युष चिकित्सक अर्बन डॉ. प्रशांत सिंह, श्रीमती राखी पाण्डेय, एएनएम अर्चना दीपांकर एवं सत्यपकाश तिवारी, अनुष्का फाउंडेशन के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

विचार

लू से 700 से अधिक मौतें

देश में आम लोगों की ज़िंदगी का कोई मोल नहीं है। कम से कम सरकारों और राजनीतिक दलों की नजर में तो बिल्कुल नजर नहीं आता। मुद्दा यदि वोट बैंक से जुड़ा हुआ हो, तभी राजनीतिक दल कुछ गंभीरता बेशक दिखा लें किन्तु लोगों के जीवन-मरण जैसे मुद्दों से लगता यही है कि उनका कोई सरोकार नहीं रह गया है। यदि ऐसा नहीं होता तो अदालतों को मौसम की मार से होने वाली मौतें रोकने के लिए सरकारों को दिशा-निर्देश नहीं देने पड़ते।

आश्चर्य की बात यह है कि प्रतिकूल मौसम से आम लोगों को बचाने की जिम्मेदारी केंद्र और राज्यों की सरकारों की है, किन्तु यह काम भी अब अदालतों को करना पड़ रहा है। इससे सवाल खड़ा होता है कि आखिर सरकारों की ज़रूरत कितनी सीमित रह गई है? हीटवेव से 700 से ज्यादा मौतों के मुद्दे पर सुप्रीमकोर्ट ने केंद्र से जवाब मांगा है। शीर्ष अदालत ने पूछा है कि इतने बड़े मौसमी संकट से निपटने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर क्या तैयारी की जा रही है। प्रधान न्यायाधीश बी.आर. गवई और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने गृह मंत्रालय, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। यह याचिका पर्यावरण कार्यकर्ता विक्रांत तोंगड़ ने दाखिल की। उन्होंने कोर्ट से गुजारिश की है कि सरकार को गर्मी की चेतावनी देने वाली प्रणाली, हीटवेव की पहले से जानकारी देने की व्यवस्था और 24 घंटे काम करने वाली राहत हैल्पलाइन जैसी सुविधाएं लागू करने के निर्देश दिए जाएं।

याचिका में यह भी बताया गया है कि 2019 में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने हीटवेव से निपटने के लिए राष्ट्रीय दिशा-निर्देश जारी किए थे, लेकिन कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने अब तक उस पर काम ही नहीं किया। याचिका में यह भी जिक्र है कि आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 35 के अनुसार केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कि वह इस तरह की आपदा से निपटने के लिए पुख्ता इंतजाम करे। इससे पहले राजस्थान हाईकोर्ट ने अधिकारियों के रवैये पर गहरी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा था कि पिछले साल दिए गए अदालत के निर्देशों को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। कोर्ट ने कहा कि यह कानून के शासन पर सवाल उठाता है। अधिकारी स्वयं को कानून से ऊपर मान रहे हैं, लेकिन कोर्ट आख बंद करके नहीं बैठ सकता। इसानों से जानवरों जैसा बर्ताव नहीं हो सकता और न जान बचाने के लिए धन की कमी का बहाना चल सकता है। कोर्ट ने मुख्य सचिव से अदालती आदेशों की पालना के लिए समन्वय समिति बनाने और लू से बचाव के लिए कार्य योजना बनाने का निर्देश दिया, वहीं केंद्रीय गृह मंत्रालय, मुख्य सचिव व राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण तथा केंद्र व राज्य सरकार के 10 अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा।

लाल आतंक के गढ़ में लहरा रहा तिरंगा

डॉ. आशीष वशिष्ठ

चार दशक से ज्यादा समय तक नसलवाद का शिकार रहे छीसगढ़ का बस्तर जिले को अब वामपंथी उग्रवादियों (एलडब्ल्यूई) जिले की सूची से बाहर कर दिया गया है। अपने आप में ये बड़ी खबर है। दरअसल मोदी सरकार का लक्ष्य है कि मार्च 2026 तक भारत पूरी तरह से नसल मुक्त हो जाए। गृह मंत्री अमित शाह भी कई बार सार्वजनिक मंच से इस बात को दोहरा चुके हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अगस्त 2024 और दिसंबर 2024 में छीसगढ़ के रायपुर और जगदलपुर आए थे। वे यहां अलग-अलग कार्यक्रमों में शामिल हुए थे। इस दौरान उन्होंने अलग-अलग मंचों से नसलियों को चेताते हुए कहा था कि हथियार डाल दें। हिंसा करोगे तो हमारे जवान निपटेंगे। वहीं उन्होंने एक डेडलाइन भी जारी की थी कि 31 मार्च 2026 तक पूरे देश से नसलवाद का खात्मा कर दिया जाएगा। शाह के डेडलाइन जारी करने के बाद से बस्तर में नसलियों के खिलाफ ऑपरेशन काफी तेज हो गए हैं।



नक्सलवाद शब्द की उत्पत्ति पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी गांव से हुई है। इसकी शुरुआत स्थानीय जमींदारों के खिलाफ विद्रोह के रूप में हुई, जिन्होंने भूमि विवाद को लेकर एक किसान की पिटाई की थी। यह आंदोलन जल्द ही पूर्वी भारत के छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश जैसे कम विकसित क्षेत्रों में फैल गया। वामपंथी उग्रवादियों (एलडब्ल्यूई) को दुनिया भर में माओवादी और भारत में नक्सलवादी के नाम से जाना जाता है। वे सशस्त्र क्रांति के माध्यम से भारत सरकार को उखाड़ फेंकने और माओवादी सिद्धांतों पर आधारित साम्यवादी राज्य की स्थापना की वकालत करते हैं। छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, बिहार, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और केरल राज्यों को वामपंथी उग्रवाद प्रभावित माना जाता है।

देश में भाजपा सरकार बनने के बाद 2015 में नक्सलवाद के खिलाफ विशेष अभियान चलाने की नीति बनाई गई। तत्कालीन गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने 8 सूत्रीय समाधान एक्शन

प्लान बनाया। इसमें नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई और नक्सली इलाकों में विकास के काम एक साथ किए गए। नक्सलियों के खिलाफ राज्य सरकारों के विशेष बल, केंद्रीय सुरक्षा बलों, पुलिस ने मिलकर कार्रवाई की। इससे नक्सली घटनाओं में जबरदस्त कमी आयी।

2010 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने जिसे भारत की सबसे बड़ी आंतरिक सुरक्षा चुनौती कहा था, वही नक्सलवाद अब खत्म होता दिख रहा है। नक्सलियों ने नेपाल के पशुपति से आंध्र प्रदेश के तिरुपति तक एक रेड कॉरिडोर स्थापित करने की योजना बनाई थी। 2013 में लगभग 126 जिलों में नक्सली सक्रिय थे। वर्तमान में नक्सलवाद से सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों की संख्या 12 से घटकर 6 हो गई। इनमें छत्तीसगढ़ के चार जिले- बीजापुर, कांकेर, नारायणपुर और सुकमा, झारखंड का एक जिला- पश्चिमी सिंहभूम और महाराष्ट्र का एक जिला- गढ़चिरोली शामिल है।

वर्ष 2025 में सुरक्षाबलों के ऑपरेशन में अब तक 287

नक्सली मारे जा चुके हैं। वहीं 865 ने समर्पण किया है और 830 गिरफ्तार हुए हैं। गत 21 मई को सुरक्षाबलों ने अबुल्ला माड़ में डेढ़ करोड़ के इनामी नंबला केशव उर्फ बसवराज को मार गिराया था। वह तीन दशक से सक्रिय था। इसे नक्सलियों का हाफिज सईद भी कहा जाता है। नक्सलियों के सरदार बसवा राजू के डेर होने के बाद माओवादियों का हौसला पस्त हो गया है। इस बड़े एनकाउंटर के बाद दक्षिण बस्तर डिवीजन में 4 हार्डकोर नक्सलियों सहित 18 माओवादियों ने सरेंडर किया था। इसी तरह बीजापुर में 32 और तेलंगाना में 86 नक्सलियों ने सरेंडर किया था। बासव राजू की मौत के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने भी एक्स पर लिखा था कि महासचिव स्तर के बड़े नक्सली नेता को मारा गया है। इस कामयाबी को हासिल करने वाला 'ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट' भी सुर्खियों में है।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नक्सलवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत वर्ष 2025 में अब तक 90 नक्सली मारे जा चुके हैं, 104 को गिरफ्तार किया गया है और 164 ने आत्मसमर्पण किया है। वर्ष 2024 में 290 नक्सलियों को न्यूट्रलाइज़ किया गया था, 1090 को गिरफ्तार किया गया और 881 ने आत्मसमर्पण किया था। अभी तक कुल 15 शीर्ष नक्सली नेताओं को न्यूट्रलाइज़ किया जा चुका है।

वर्ष 2004 से 2014 के बीच नक्सली हिंसा की कुल 16,463 घटनाएं हुई थीं, जबकि मोदी सरकार के कार्यकाल में 2014 से 2024 के बीच हिंसक घटनाओं की संख्या 53 प्रतिशत घटकर 7,744 रह गई हैं। इसी प्रकार, सुरक्षाबलों की मृत्यु की संख्या 1851 से 73 प्रतिशत घटकर 509 रह गई और नागरिकों की मृत्यु की संख्या 70 प्रतिशत की कमी के साथ 4766 से 1495 रह गई है।

वर्ष 2014 तक कुल 66 फोर्टिफाइड पुलिस स्टेशन थे जबकि मोदी सरकार के पिछले 10 साल के कार्यकाल में इनकी संख्या बढ़कर 612 हो गई है। इसी प्रकार, 2014 में देश में 126 जिले नक्सल प्रभावित थे, लेकिन 2024 में सबसे अधिक प्रभावित जिलों की संख्या घटकर मात्र 12 रह गई है। पिछले 5 वर्षों में कुल 302 नए सुरक्षा कैंप और 68 नाइट लैंडिंग हेलीपैड बनाए गए हैं।

नक्सली हिंसा में 2010 में 720 नागरिक मारे गए। 2024 में मरने वालों की संख्या घटकर 131 हो गई। नक्सली हिंसा में 2010 में 1005 नागरिक और सुरक्षा बल मारे गए। 2024 में 150 नागरिक और सुरक्षा बल मारे गए। यानि कि मरने वालों की संख्या में 85 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई। नक्सली आर्थिक ढांचे जैसे कि रेलवे प्रॉपर्टी, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर की इकाइयों, टेलीफोन एक्सचेंज, मोबाइल टॉवर, सड़क, स्कूल को निशाना बनाते रहे हैं। पर पिछले कुछ साल से इन घटनाओं में कमी आई है। 2010 में हमले की ऐसे 365 मामले थे, जो 2024 में घटकर 25 रह गए।

पिछले एक दशक में मिली सफलता का श्रेय सुरक्षा रणनीति के साथ ही विकास योजनाओं में आई तेजी को भी जाता है। सरकार ने लक्षित विकास योजनाएं चलाई, जिनसे लोगों का भरोसा दोबारा जीता जा सका। सड़क और मोबाइल नेटवर्क जैसी बुनियादी सुविधाओं में काफी सुधार हुआ है। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के कामों ने स्थानीय लोगों के दिलों में जगह बनाई है। वहीं, 'रोशनी योजना' ने आदिवासी युवाओं को कोशल विकास और रोजगार प्राप्त करने में मदद की है।

केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि वह उन मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के दबाव में नहीं आएगी, जो बंदूक उठाने वाले माओवादी उग्रवादियों का समर्थन करते हैं। पिछले एक दशक से सरकार ने माओवाद के खिलाफ एक मजबूत और बहुआयामी रणनीति अपनाई है, जो अब काफी असरदार साबित हो रही है। गृह मंत्रालय की 2017 में शुरू की गई 'समाधान' रणनीति ने जमीन पर बड़ा फर्क डाला है। इसमें सुरक्षा संबंधी कार्ययोजना के साथ-साथ विकास से जुड़ी पहल भी शामिल है।

नक्सलियों के खिलाफ अभियान मोदी सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति का प्रतीक है। इस से पहले कोई सरकार ऐसी इच्छाशक्ति दिखा नहीं पाई। ध्यान इस बात का रखना होगा कि नक्सलवाद फिर फिर न उठा पाए, इसके लिए प्रभावित इलाकों में अगला चरण लोकानुखी सरकार, भूमि अधिकार, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और आर्थिक उत्थान पर फोकस होना चाहिए। जमीनी लड़ाई में जीत केवल आधी सफलता है, अगला फोकस नक्सलियों के पुनर्वास और उन्हें मुख्यधारा में शामिल करने पर होना चाहिए। जिस तरह मोदी सरकार नक्सली समस्या को खत्म काने कि दिशा में तेजी से बाद रही है उम्मीद है कि वो 2026 में समस्या के स्थायी समाधान के साथ देश के सामने गर्व से खड़ी होगी।

संवाद और संचार की दुनिया में बज रहा हिंदी का डंका

प्रो. संजय द्विवेदी
कोलकाता से 200 साल पहले जब पं. युगलकिशोर शुक्ल ने हिंदी का पहला पत्र 30 मई, 1826 को प्रारंभ किया होगा, तो उन्होंने यह सोचा भी न होगा कि हिंदी पत्रकारिता देश की आवाज बन जाएगी।? वह इस महान देश के सपनों, आकांक्षाओं, संघर्षों, आंदोलनों, दुखों और आर्तनाद की सबसे प्रखर भाषा की वाहक बनेगी। हिंदी पत्रकारिता के पहले संपादक का सपना था, हमारी पत्रकारिता %हिंदुस्तानियों के हित के हेतु% हो। यह वाक्य उन्होंने अपने पहले संपादकीय में लिखा और हमें हमारा संकल्प बता दिया। हमारी कृतध्ता देखिए कि इस महान नायक की स्मृति में देश में कोई स्मारक नहीं है। न कोलकाता में, न ही उनकी जन्मस्थली पर। अपने पुरखों के प्रति हम कितने लापरवाही से भरे हुए हैं, उसका उदाहरण है कि शुक्ल जी का कोई चित्र हमारे पास नहीं है। इसलिए %उर्दत मार्तण्ड% का पृष्ठ लगाकर उन्हें याद करते हैं। हद तो तब हो गई जब दो-तीन वर्षों से युगल किशोर शुक्ल के नाम पर हिंदी पत्रकारिता दिवस पर अनेक अखबारों में साहित्यकार श्री शिवपूजन सहाय के चित्र छपे जा रहे हैं। आज भी गूगल में सर्च करने पर शुक्ल जी के नाम पर सहाय जी का चित्र आंखों के सामने तैरता है। मैंने भारतीय जन संचार संस्थान (आईआईएमसी) में अपनी पदस्थापना के दौरान वहां के पुस्तकालय और वाचनालय का नामकरण शुक्ल जी के

नाम पर किया। वह देश में उनकी स्मृति में पहला स्मारक था। यह तो रही हमारी स्मृति हीनता की बात। लेकिन शुक्ल जी रोपा पौधा आज लहलहा रहा है।

हिंदी पत्रकारिता देश की सबसे खास आवाज बन चुकी है। इसके साथ ही संचार और संवाद की हिंदी सबसे खास भाषा है। सिर्फ पत्रकारिता से नहीं अपने विविध माध्यमों पर उपलब्ध कंटेंट से हिंदी को बड़ा आधार मिला है।

रजिस्ट्रार आफ न्यूजपर्स फार इंडिया (आरएनआई) 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 1 लाख, 47 हजार से अधिक पत्र-पत्रिकाएं पंजीकृत हैं, जिनमें 45 प्रतिशत हिंदी के हैं। इंडियन रीडरशिप सर्वे की मानें तो हिंदी अखबारों की पाठक संख्या 38 करोड़ से अधिक है। भारत में 750 से अधिक टीवी चैनल हैं , जिनमें 35 प्रतिशत हिंदी के हैं। ये आंकड़े बताते हैं हिंदी पत्रकारिता ने एक लंबी यात्रा में अपना सामाजिक आधार विस्तृत किया है।

डिजिटल दुनिया में राज कर रही हिंदी

हिंदी पत्रकारिता का विस्तार अब डिजिटल दुनिया में भी संभव हुआ है। डिजिटल का सूरज कभी डूबता नहीं और जो डिजिटल पर है, वह ग्लोबल होने की संभावना से भरा हुआ है। इस दुनिया में भी हिंदी का डंका बज रहा है। गूगल और केपीएनजी की 2024 की रिपोर्ट बताती है कि भारत में इंटरनेट उपभोक्ता अब 85 करोड़ से अधिक हैं। इनमें 70 प्रतिशत भारतीय भाषाओं, विशेषकर हिंदी में



सामग्री पढ़ना, सुनना, देखना चाहते हैं। हिंदी डिजिटल का बाजार हर साल 20 प्रतिशत की दर से बढ़ रहा है। 2024 के आंकड़े बताते हैं कि 75 प्रतिशत से अधिक वीडियो कंटेंट हिंदी और भारतीय भाषाओं में देखे जा रहे हैं। नए समय में ए-आई, भाषा माडल्स और वायस टू

टेक्स्ट तकनीक से हिंदी कंटेंट को बहुत बढ़ावा मिल रहा। कल तक हिंदी टेक्स्ट को पढ़ने में कठिनाइयां महसूस कर रहे लोग दुनिया भर में हिंदी कंटेंट को सुन और देख रहे हैं। 2016 में डिजिटल माध्यम पर हिंदी पढ़ने वालों की संख्या 5.5 करोड़ थी, जो 2025 में बढ़कर 15.6

करोड़ होने का अनुमान है।

सोशल मीडिया पर भी दमदार उपस्थिति

हिंदी में हर माह 10 अरब घंटे से ज्यादा वीडियो देखे जाने का आंकड़ा बताता है भाषा का विस्तार, शक्ति और गहराई क्या है। देश में यूट्यूब के

उपयोगकर्ताओं की संख्या 50 करोड़ से ऊपर है, जो इसे संभव बनाते हैं। भारत में इंस्टाग्राम के 30 करोड़ उपयोगकर्ताओं ने संचार की दुनिया में गहरा हस्तक्षेप किया। इंस्टा पर हिंदी रील्स की औसत व्यूवरशिप अंग्रेजी के मुकाबले दोगुनी से अधिक है। यूट्यूब और इंस्टा पर हिंदी कंटेंट बनाने वालों की संख्या भी 2020 के मुकाबले दोगुनी हो गई है। वायस सर्च में हिंदी का उपयोग उसे विस्तार दे रहा है।

ओटीटी पर हिंदी राज

कोरोना में मनोरंजन संचार की सबसे बड़ी घटना थी, ओटीटी कंटेंट का विस्तार और स्वीकार। आज भारत में यह लगभग 23,000 करोड़ रुपए का बाजार है। अनुमान है कि 2027 तक यह 40,000 करोड़ का हो जाएगा। भारत में ओटीटी के 50 करोड़ से अधिक उपभोक्ता हैं, जिनमें 70 से अधिक हिन्दी भाषी हैं। कंपनियां सबसे ज्यादा ओरिजनल कंटेंट हिंदी में बना रही हैं। समग्रता में देखें तो 1826 में एक पत्र चलाना कितना कठिन था। शुक्ल जी उसे दो साल भी नहीं चला सके। आज इतने सारे संचार माध्यमों पर राज कर रही हिंदी का विस्तार देखकर उनकी आत्मा निश्चित ही प्रसन्न होकर संचार के साधकों पर आशीर्वाद की वर्षा कर रही होगी। अब जबकि हम हिन्दी पत्रकारिता के 200 साल पूरे करने जा रहे हैं, तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने सभी संचार माध्यमों को ज्यादा जनपक्षधर, मानवीय, संवेदनशील, अश्लील सामग्री मुक्त और विमर्श का केंद्र बनाएं।

"कृषि आउटरीच" कार्यक्रम के तहत किसानों और महिलाओं को मिला करोड़ों का ऋण समर्थन

मीडिया ऑडीटर, एमसीबी (निप्र)। जिले के मनेन्द्रगढ़ स्थित पंजाब नेशनल बैंक शाखा में 2 जून को एक विशेष कार्यक्रम "कृषि आउटरीच" का आयोजन भव्य रूप से किया गया। यह कार्यक्रम किसानों, महिला स्व-सहायता समूहों तथा स्थानीय उद्यमियों को बैंकिंग सुविधाओं से जोड़ने और उन्हें वित्तीय रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से आयोजित किया गया था। कार्यक्रम में मंडल कार्यालय बिलासपुर से उप मंडल प्रमुख श्री दिव्य रंजन नायक की गरिमामयी उपस्थिति रही, जिन्होंने बैंक की इस पहल की सराहना की और ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि एवं स्वरोजगार को बढ़ावा देने हेतु बैंकिंग संस्थाओं की भूमिका को रेखांकित किया। इस कार्यक्रम में जिला कार्यक्रम प्रबंधक एनआरएलएम रितेश पाटीदार, जिला पंचायत से राजेश जैन, पंजाब नेशनल बैंक मनेन्द्रगढ़ के शाखा प्रबंधक ब्रज मोहन भारती, कृषि विभाग से



धनेश्वर वाबले, उप शाखा प्रबंधक नवल किशोर साहू, उप प्रबंधक राजेश कुमार, विकास विक्रम, अनिस सीमा तिगा, प्रदीप देवांगन, दिनेश कुमार एवं दीपा दत्ता सहित कई अन्य गणमान्य अधिकारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान पंजाब नेशनल

बैंक द्वारा विभिन्न ऋण योजनाओं के अंतर्गत उल्लेखनीय स्वीकृतियाँ प्रदान की गईं। बैंक द्वारा पीएमएफएमई (प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना) के अंतर्गत 4 ऋण स्वीकृत किए गए जिनकी कुल राशि 26 लाख रही।

महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक अहम कदम उठाते हुए 11 स्वयं सहायता समूहों को कुल 48 लाख के ऋण स्वीकृत किए गए। इसके अतिरिक्त 5 लखपति दीदी योजना के अंतर्गत कुल 4.5 लाख के ऋण प्रदान किए गये। जिससे महिलाओं के



आर्थिक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिलेगा। किसानों को कृषि कार्यों हेतु सशक्त करने के उद्देश्य से 1 केसीसी (किसान क्रेडिट कार्ड) ऋण 3 लाख का भी स्वीकृत किया गया। ऋण स्वीकृति ही नहीं, बल्कि इस कार्यक्रम के दौरान भविष्य की संभावनाओं को

भी मजबूती दी गई। बैंक द्वारा दो संभावित राइस मिल परियोजनाओं के लिए लगभग 22 करोड़ के ऋण सीस किए गये। जिससे जिले में कृषि आधारित उद्योगों को नया जीवन और किसानों को विपणन के बेहतर अवसर प्राप्त होंगे।

एकलव्य विद्यालय प्रवेश 2025-26 हेतु चयनित विद्यार्थियों को अंतिम काउंसलिंग

एकलव्य विद्यालय प्रवेश हेतु अनुपस्थित विद्यार्थियों के लिए 5 एवं 6 जून को अंतिम काउंसलिंग

मीडिया ऑडीटर, एमसीबी (निप्र)। जिले में संचालित एकलव्य संयुक्त आदर्श आवासीय विद्यालयों में कक्षा 6 वीं में प्रवेश हेतु वर्ष 2025-26 के लिए चयनित विद्यार्थियों की अंतिम मेरिट सूची के आधार पर काउंसलिंग 16 मई से 17 मई 2025 तक एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, पोड़ीडीह, जिला एमसीबी के ऑडिटोरियम कक्ष में आयोजित की गई थी। इस काउंसलिंग में जो विद्यार्थी उपस्थित नहीं हो सके थे, उन्हें एक

और अंतिम अवसर प्रदान किया जा रहा है। ऐसे विद्यार्थियों की काउंसलिंग 5 जून एवं 6 जून 2025 को आयोजित की जाएगी, जिसमें खडगवा विकासखण्ड के विद्यार्थियों की काउंसलिंग एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय जमथान में संपन्न होगी। जिन विद्यार्थियों की पूर्व में उपस्थिति नहीं हो सकी थी, यदि वे इस अवसर पर भी अनुपस्थित रहते हैं, तो उनकी रिक्त सीटों की पूर्ति प्रतीक्षा सूची में शामिल विद्यार्थियों की काउंसलिंग के माध्यम से की जाएगी। काउंसलिंग में उपस्थित होने वाले विद्यार्थियों को अपने साथ मूल निवास प्रमाण पत्र, स्थायी जाति प्रमाण पत्र (केवल अनुसूचित जनजाति हेतु), आधार कार्ड की

छायाप्रति, सिकल सेल का शासकीय चिकित्सक द्वारा जारी प्रमाण पत्र, विशेष श्रेणियों जैसे वामपंथी उग्रवाद/विद्रोह/कोविड से माता-पिता को खो चुके बच्चे, विधवाओं के बच्चे, दिव्यांग माता-पिता के बच्चे, भूमि दान करने वाले परिवारों के बच्चे, अनाथ बच्चे, पुलिस/अर्धसैनिक/सशस्त्र बलों के शहीद जवानों के बच्चे एवं दिव्यांग बच्चों हेतु सम्बन्धित प्रमाण-पत्र, विशेष शासकीय कर्मचारी के बच्चों का प्रमाण-पत्र एवं जिला चिकित्सालय बोर्ड (जे अनुपस्थित रहते हैं, तो उनकी रिक्त सीटों की पूर्ति प्रतीक्षा सूची में शामिल विद्यार्थियों की काउंसलिंग के माध्यम से की जाएगी। काउंसलिंग में उपस्थित होने वाले विद्यार्थियों को अपने साथ मूल निवास प्रमाण पत्र, स्थायी जाति प्रमाण पत्र (केवल अनुसूचित जनजाति हेतु), आधार कार्ड की

जनदर्शन में आए 45 आवेदन, अपर कलेक्टर ने विभागों को त्वरित निराकरण करने के लिए निर्देश

मीडिया ऑडीटर, एमसीबी (निप्र)। कलेक्टर डी. राहुल वैकट के निर्देशन पर अपर कलेक्टर अनिल कुमार सिद्ध ने आज कलेक्ट्रेट कार्यालय में जनदर्शन के माध्यम से आम नागरिकों की समस्याओं को सुना। जिले के ग्रामीण जन और नागरिकों ने जनदर्शन में अपनी छोटी-बड़ी समस्याओं को सीधे अपर कलेक्टर के समक्ष रखा। अपर कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को प्राप्त सभी आवेदनों को प्राथमिकता के साथ शीघ्रता से समय-सीमा में निराकरण करने के निर्देश दिए हैं। आज की जनदर्शन में कुल 45 आवेदन प्राप्त हुए। इस जनदर्शन में आवेदक सुमन बाई, भानु प्रकाश सिंह, शंकर, अमीरा सिंह, बाबू लाल, राजेश, राजन, दल प्रताप सिंह, सुभद्री, समयलाल, कुंवार सिंह, मानिक चंद साहू, गणेश साहू, विनय प्रताप सिंह और कैलसिया ने भूमि के संबंध में आवेदन दिये। इसी के साथ

शिवनारायण सिंह, शिवप्रसाद सुखनन्दन,दुर्गा प्रसाद, हीरा सिंह, विक्रम, और उमेश सिंह ने नामांतरण, सीमांकन, नक्शा खसरा सुधार, बी 1 के संबंध में अपना आवेदन प्रस्तुत किया था। इसके साथ ही अभय बड़ा ने सुशासन तिहार 2025 में दिए गए आवेदनों पर कार्यवाही नहीं होने के संबंध में, जगदेव सिंह ने कूप निर्माण के संबंध में, रवी प्रसाद निवासी नई लेदरी ने बिना सूचना दिए कार्य से निकाल दिए जाने के संबंध में, राजेश पनिका और शंकर ने ट्रायल सायकल की मांग के संबंध में, सरजू रजक ने हेंडपंप के संबंध में, रीमा यादव निवासी झगराखांड ने विभाग से होने वाली कार्यों की जानकारी देने, ओपन जिमदार स्थापित करने और आंगनवाड़ी स्थापित करने के संबंध में, अभिनव द्विवेदी ने राशन दुकान में मिट्टी तेल आपूर्ति के संबंध में, योगेन्द्र सिंह ने विद्युत कनेक्शन न दिए जाने के संबंध में, सुमेर ने

तालाब गहरीकरण के संबंध में, इतवार सिंह ने वृद्धा पेंशन स्वीकृति कराने के संबंध में, राधेश्याम ने स्टॉप डेम में लिकेज हो रहा है उसके संबंध में, किसुन सिंह ने स्थान के संबंध में, सुरेश साहू नियमित भूत्य, चौकीदार कर्मचारियों को प्रथम समयमान वेतनमान देने के संबंध में, समस्त सहायिका कार्यकर्ता कछोड़ ने प्रतापित करने के संबंध में, मोहम्मद सद्दाम मनेन्द्रगढ़ ने लिपिक दशोदिया द्वारा रिश्तत मानने के संबंध में, चुनिता जांगड़े ने बकाया राशि के संबंध में, समस्त ग्रामवासी नामपुर सीसीटीवी कैमरा एवं स्पीड कंट्रोलर ट्रैफिक सिग्नल लगाने के संबंध में और बाउंड्री वाल निर्माण के संबंध में अपनी शिकायत लेकर उपस्थित हुए थे। अपर कलेक्टर ने प्राप्त सभी आवेदनों को पूरी गंभीरता से सुनते हुए संबंधित विभागों को उचित कार्यवाही करते हुए त्वरित निराकरण करने के निर्देश दिए।

कमिश्नर, आईजी, डीआईजी और कलेक्टर ने लिया तैयारियों का जायजा

मुख्यमंत्री आज आयेंगे रीवा, गंगेव में महिला स्वसहायता समूहों के सम्मेलन में होंगे शामिल

मीडिया ऑडीटर, रीवा (निप्र)। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव 4 जून को रीवा जिले के मनगवां विधानसभा क्षेत्र के गंगेव आएंगे। मुख्यमंत्री डॉ यादव रीवा के गंगेव में आयोजित महिला स्वसहायता समूह के सशक्तिकरण सम्मेलन में शामिल होंगे। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मुख्यमंत्री डॉ यादव सुबह 11.55 बजे भोपाल से वायुयान से प्रस्थान कर दोपहर 12.30 बजे डुमना एयरपोर्ट जबलपुर पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री जबलपुर से हेलीकाप्टर द्वारा दोपहर 12.35 बजे प्रस्थान कर 1.30 बजे उमरिया जिले के पाली पहुंचकर स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री दोपहर 3 बजे पाली से हेलीकाप्टर से प्रस्थान कर दोपहर बाद 3.45 बजे हेलीपैड गंगेव पहुंचेंगे।

मुख्यमंत्री गंगेव स्टेडियम में आयोजित विशाल महिला स्वसहायता समूह कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री कार्यक्रम स्थल पर पहुंचकर कन्या पूजन और दीप प्रज्वलन कर महिला स्वसहायता समूहों के सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विद्युत चलित शैलावाक से निर्मित मिट्टी के बर्तनों का अवलोकन एवं वितरण कर हितग्राहियों से चर्चा करेंगे। कार्यक्रम में अतिथियों के स्वागत के बाद मनगवां विधायक श्री नरेन्द्र प्रजापति स्वागत उद्बोधन देंगे। इसके बाद सांसद श्री जर्नार्दन मिश्र का उद्बोधन होगा। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ यादव विकास कार्यों का वर्चुअल लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल तथा पंचायत एवं ग्रामीण विकास तथा श्रम मंत्री और रीवा



जिले के प्रभारी मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल का उद्बोधन होगा। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव आजीविका उन्नयन के द्वारा आर्थिक रूप सशक्त हुई स्वसहायता समूहों की महिलाओं से संवाद करेंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। कार्यक्रम में इसके बाद मुख्यमंत्री हितग्राहियों को हितलाभा का वितरण करेंगे। कार्यक्रम का समापन आभार प्रदर्शन से होगा।

मुख्यमंत्री गंगेव स्टेडियम में आयोजित महिला स्वसहायता समूह सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होकर विभिन्न योजनाओं से निकाय मितिकर पेयजल की समुचित व्यवस्था करें। प्रत्येक सेक्टर में एक अधिकारी और कर्मचारी पेयजल की आपूर्ति के लिए तैनात रखें। सभी सेक्टर में कार्यपालिक मजिस्ट्रेट तथा पुलिस अधिकारी कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए समुचित प्रबंध करें। कमिश्नर ने अधिकारियों को

मंच व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था, यातायात प्रबंधन तथा साउंड व्यवस्था के संबंध में निर्देश दिए। इस अवसर पर जनपद पंचायत गंगेव के अध्यक्ष श्री विकास तिवारी आयुक्त नगर निगम डॉ सौरभ सोनवड़े, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी मेहाबत सिंह गुर्जर, अपर कलेक्टर सपना निपाटी, प्रभारी पुलिस अधीक्षक विवेक लाल तथा प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस अधिकारी एवं अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री 49.97 करोड़ रुपए के निर्माण कार्यों का करेंगे शिलान्यास और लोकार्पण: मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव मनगवां विधानसभा क्षेत्र में आयोजित महिला स्वसहायता समूह सशक्तिकरण समारोह में 49 करोड़ 97 लाख रुपए के कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। मुख्यमंत्री डॉ यादव 29 करोड़ 39 लाख रुपए की लागत के 6 निर्माण

कार्यों का शिलान्यास करेंगे। मुख्यमंत्री मनगवां विधानसभा क्षेत्र में 10 उप स्वास्थ्य केन्द्र भवनों के निर्माण कार्यों का शिलान्यास करेंगे। इनमें उप स्वास्थ्य केन्द्र भवन भदावल, छत्रगढ़, कोट, हकरिया, अमहा, बेलवा पैकान, घोषी, जोरौट, परासी तथा रक्सामाजन शामिल हैं। इनकी कुल लागत 6 करोड़ 50 लाख रुपए है। प्रत्येक उप स्वास्थ्य केन्द्र भवन के लिए 65 लाख रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के तहत 6 करोड़ 16 लाख रुपए की लागत से बनाए जाने वाले 11 अमृत सरोवर, एक करोड़ पाँच लाख रुपए की लागत से बनाए जाने वाले 7 सामुदायिक पार्क और एक करोड़ 25 लाख रुपए की लागत से बनाए जाने वाले 5 सामुदायिक भवनों के निर्माण कार्यों का शिलान्यास करेंगे। मुख्यमंत्री 4 करोड़ 48 लाख रुपए की लागत से बनने वाली जोधपुर नम्बर एक से

सतना की खबरें

मैहर सांस्कृतिक एवं धार्मिक परिक्षेत्र - देवप्रवर



मीडिया ऑडीटर, मैहर (निप्र)। रामजानकी शक्तिपीठ पुरानीलंका चित्रकूट पीठाधीश्वर रामानुजाचार्य श्रीमद जगतगुरु के कृपापत्र शिष्य पूर्व शिक्षक मोलेराम तिवारी के निज निवास वार्ड नंबर 12 विवेक नगर मैहर में आयोजित श्रीमद भागवत ज्ञान यज्ञ सप्ताह में पुरानीलंका शक्तिपीठ के युवराज स्वामी रामानुजाचार्य श्रीमद जगतगुरु देवप्रवर प्रपन्नाचार्य के श्रीमुरु से प्रवाहित ज्ञान गंगा के छठवें दिवस में युवराज स्वामी ने कथा के अनेक प्रसंगों से उपस्थित जनमानस को किया भाव विभोर। धर्म नगरी मैहर के सांस्कृतिक एवं धार्मिक परिक्षेत्र की चर्चा करते हुए कहा कि मातृ शक्ति पीठ साक्षात् शक्ति स्वरूपा मां शारदा देवी से लेकर नीलकंठ महाप्रभु भगवान भोलेनाथ, उत्तर, पूर्व में विंध्य पर्वत श्रृंखला से प्रवाहित जीवन दायिनी सलिला मां तमसा के तट में स्थित सिद्ध बाबा जो नाम से ही कर्मयोग क्षेत्र सिद्ध होता है। स्वाभाविक रूप से यहां

का जनमानस पुण्यात्मा है। अतिशयोक्ति नहीं हो तो कहें कुछ ही दिनों में यह क्षेत्र पर्यटक स्थल के रूप में स्थापित होने वाला है। देश विदेश के पर्यटक और समीत साधक हमारी इस सांस्कृतिक धार्मिक धरोहर को देखने सुनने के लिए मैहर क्षेत्र में आकर मैं का हरण करते मिलेंगे। वरुण भगवान प्रसंग, गोपी प्रसंग के साथ युवराज स्वामी ने रुक्मिणीकृष्ण विवाह की घोषणा मंच से की तभी पुष्प वर्षा के साथ भक्त समूह करतल ध्वनि से विवाह गीतों के साथ झूमते गाते नाचते नजर आए। श्री राधे राधे के जयघोष के साथ कथा का विश्राम हुआ।

आज की कथा में प्रमुखरूप पंडित रामनिवास उमाविल्या, राजगुरु मनोज अग्निहोत्री, गबलू पटनवाह, गंगा प्रताप सिंह लखनवाह, शीलू पटनवाह, अफसर सकरिया, बबलू तिवारी, फिल्म एक्टर शीलकंठ बाय, मदन सोनी के साथ तिवारी परिवार एवं क्षेत्रीय जनमानस उपस्थित रहा।

राष्ट्रीय स्तरीय सतत पुनर्वास प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ



मीडिया ऑडीटर, रीवा/सतना (निप्र)। राष्ट्रीय विजय सिंह मेमोरियल ट्रेनिंग, रिसर्च एवं पुनर्वास संस्थान, रीवा (म.प्र.) में भारतीय पुनर्वास परिषद , सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार तथा राष्ट्रीय न्यास के संयुक्त तत्वावधान में बौद्धिक दिव्यांगता एवं बहु दिव्यांगता से संबंधित बच्चों हेतु तीन दिवसीय राष्ट्रीय स्तरीय सतत पुनर्वास कार्यक्रम (छ्त्र) का शुभारंभ 2 जून से किया गया। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम 2, 3 एवं 4 जून 2025 तक आयोजित किया जा रहा है। जिसका विषय है "बौद्धिक दिव्यांग एवं बहु दिव्यांग बच्चों के लिए विभिन्न प्रकार की चिकित्सा अनुसूची थैरेपी के बारे में अवगत कराना"। कार्यक्रम की शुरुआत माँ सरस्वती की वंदना एवं माल्यार्पण से हुई। इसके पश्चात विषय विशेषज्ञों द्वारा विभिन्न चिकित्सा पद्धतियों एवं पुनर्वास विषयों पर विस्तृत जानकारी दी गई। इस अवसर पर ब्रह्माकुमारी

ईश्वरिया विश्वविद्यालय से आई हुई भी की निर्मला दीदी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थिति रही। कार्यक्रम में विशेष उपस्थिति में, श्रीमती रानी सिंह (संस्थापिका), श्री अजय सिंह (अध्यक्ष), श्री संजय सिंह (सचिव), श्रीमती दीपति सिंह परिहार (संचालिका) दिवाकर सिंह (सं.क वारर (नैदानिक मनोचिकित्सक) डा विभा श्रीवास्तव (प्राचार्य), डॉ.महेश मानी द्विवेदी, श्री रमेश कुमार निपाटी (प्राचार्य), श्री संजय दुबे (सामाजिक कार्यकर्ता), श्री अनिरुद्ध यादव (रिसोर्स पर्सन), है डॉ. दिलीप विषय है" बौद्धिक दिव्यांग एवं बहु दिव्यांग बच्चों के लिए विभिन्न प्रकार की चिकित्सा अनुसूची थैरेपी के बारे में अवगत कराना"। कार्यक्रम की शुरुआत माँ सरस्वती की वंदना एवं माल्यार्पण से हुई। इसके पश्चात विषय विशेषज्ञों द्वारा विभिन्न चिकित्सा पद्धतियों एवं पुनर्वास विषयों पर विस्तृत जानकारी दी गई। इस अवसर पर ब्रह्माकुमारी

भारत विकास परिषद व इनरव्हील ने किया सेमिनार



मीडिया ऑडीटर, सतना (निप्र)। मंगलवार को भारत विकास परिषद मातृशक्ति एवं इनर व्हील उदगम सतना के संयुक्त तत्वाधान में स्थानीय शासकीय आई टी आई महाविद्यालय में एक सेमिनार आयोजित हुआ। भारत विकास परिषद उपाध्यक्ष मातृ शक्ति प्रमुख एडवोकेट आभा अग्रवाल ने अपने प्रारंभिक उद्बोधन में कहा कि युवाओं में आजकल एक अलग तरह का तनाव एवं दबाव देखा जा रहा है जिस के कारण उनके अंदर एक अस्तित्व जागृत हो रहा है और वे विद्रोही स्वभाव के हो रहे हैं जिसका समाधान होना अति आवश्यक है।भारत विकास परिषद और इनर व्हील द्वारा आयोजित इस सेमिनार में जिसका विषय "आधुनिक जीवन में किशोरों एवं युवाओं में पोषण एवं स्वस्थ जीवनशैली का महत्व" था। इस सेमिनार में विद्यार्थियों को मुंहई से आई द्वाहा

प्रमाणित न्यूट्रीशनलिस्ट श्रीमती स्वर्णिम केशरी और श्रीमती रीमा खंडेलवाल ने विद्यार्थियों को स्वस्थ दिनचर्या एवं सम्पूर्ण पोषक आहार के बारे में रोचक एवं महत्वपूर्ण जानकारी दी। प्राचार्य श्री बी डी तिवारी जी ने इस सेमिनार को बहुत ही लाभप्रद बताया उन्होंने कहा कि भारतीय भोजन ही सर्वश्रेष्ठ है। इनर व्हील उदगम अध्यक्ष श्रीमती पलक केकरावानी के विशेष प्रयास से ये कार्यक्रम सफलता पूर्वक सम्पन्न हुआ।रेतु तिवारी, श्रीमती क्रांति जैन, श्रीमति श्रेया ताम्रकार, इत्यादि ने अपना सक्रिय सहयोग दिया। आभार प्रदर्शन सह सचिव श्रीमती अनमोल केशवानी द्वारा व्यक्त किया गया इस सेमिनार के सफलता पूर्वक संपादन में दोनों संस्थानों की पदाधिकारी एवं मातृ शक्ति बहनें , महाविद्यालय के प्राचार्य एवं सभी टीचर्स का पूर्ण योगदान रहा।

सीडीएस बोले-पाक भारत को 48 घंटे में हतना चाहता था

नई दिल्ली (एजेंसी)। पुणे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने मंगलवार को पहलगाम आतंकी हमला और ऑपरेशन सिंदूर पर बात की। वे मंगलवार को पुणे यूनिवर्सिटी पहुंचे थे। उन्होंने यहां भविष्य के युद्ध और युद्ध विषय पर व्याख्यान दिया। उन्होंने कहा, 10 मई रात 1 बजे पाकिस्तान ने भारत को 48 घंटे में घुटने पर लाने की प्लानिंग की थी, उसने कई जगह पर एक साथ हमले किए और संघर्ष को बढ़ाया, लेकिन उसकी योजना 8 घंटे में ही फेल हो गई थी। इसके बाद बड़े नुकसान के डर से सीजफायर के लिए कॉल किया। हमने केवल आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया था। उन्होंने कहा, भारत आतंक और न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग को छाया में रहने वाला नहीं है। प्रोफेशनल मिलिट्री फोर्स पर असफलताओं और नुकसान का असर नहीं पड़ता। आपको अपना मनोबल बनाए रखने की जरूरत है। नुकसान महत्वपूर्ण नहीं हैं, बल्कि परिणाम महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने कहा कि पहलगाम में जो कुछ हुआ उससे कुछ हफ्ते पहले ही पाकिस्तान आर्मी चीफ जनरल असोम मुनीर ने भारत और हिंदुओं के खिलाफ जहर उगला था। पहलगाम में जो हुआ वह पीड़ितों के लिए घोर क़रूरता थी। ऑपरेशन सिंदूर के पीछे सोच यह थी कि पाकिस्तान से राज्य प्रायोजित आतंकवाद को रोकना है।

आर्मी ऑफिसरों की प्राइवेटरी पर सरकार की एडवाइजरी

नई दिल्ली। रक्षा मंत्रालय ने मंगलवार को मीडिया और लोगों से अपील की है कि वे सीनियर सैन्य अधिकारियों और उनके परिवारों की गोपनीयता का सम्मान करें। सरकार ने एडवाइजरी में लिखा, सेवारत या रिटायर्ड सैन्य अधिकारियों के निजी आवासों या परिवारों से इंटरव्यू करने से बचें। डिफेंस मिनिस्ट्री ने एडवाइजरी में कहा है कि जब तक आधिकारिक तरीके से इसका इन्विटेशन या इजाजत न दी गई हो, तब तक आवासीय पते, परिवार के सदस्यों की तस्वीरें या अन्य निजी व्थीरों का छापने या प्रसारित करने से बचें। मंत्रालय ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान और उसके बाद सैन्य गतिविधियों से जुड़ी जानकारी देने के लिए समय-समय पर कई अफसर मीडिया के सामने आए। इन अफसरों को लेकर हो रही लगातार कवरेज उनके परिवारों के लोगों और निजी जिंदगी तक पहुंच गई। मीडियाकर्मियों ने कथित तौर पर उनके आवास पर जाकर उनके परिवार के सदस्यों से संपर्क साधने की कोशिश की। इसके अलावा सेना के अफसरों के परिवार से आधिकारिक नहीं, बल्कि सांकेतिक मुद्दे पर कवरेज की गई।

कर्नाटक हाईकोर्ट ने कमल हासन को फटकारा
चेन्नई (एजेंसी)। कमल ने 24 मई को कहा था कि कन्नड़ भाषा तमिल से पैदा हुई है। इसके बाद कर्नाटक में लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए उनसे माफी मांगने की मांग की जा रही है।

ऑपरेशन सिंदूर पर इंडिया ब्लॉक की बैठक, 16 दल शामिल

नई दिल्ली (एजेंसी)। ऑपरेशन सिंदूर पर संसद का विशेष सत्र बुलाने के लिए इंडियू ब्लॉक की मंगलवार को नई दिल्ली में बैठक हुई। इसमें 16 विपक्षी पार्टियाँ ने हिस्सा लिया। टीएमपीसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने जानकारी दी कि सभी दलों ने पीएम को, पत्र लिखकर संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की गई है। आम आदमी पार्टी मीटिंग में शामिल नहीं हुई। डेरेक ने बताया कि, ऋतुधर को प्रधानमंत्री को अलग से चिट्ठी भेजेगी। बैठक में कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, तृणमूल

कांग्रेस, द्रविड़ मुनेत्र कडगम, शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे), राष्ट्रीय जनता दल, जम्मू-कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी), इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा, विद्रुथलाई चिरूथैगल काची, केरल कांग्रेस, मरुमलार्ची द्रविड़ मुनेत्र कडगम, और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी-लेनिनवादी) लिबरेशन शामिल हुई।

पाक के लिए जासूसी के शक में पंजाब से गिरफ्तारी

तरनतारन (एजेंसी)। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के शक में पंजाब के तरनतारन से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। आरोप है कि वह ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी सैन्य जानकारीयां पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी को भेज रहा था। आरोपी की पहचान तरनतारन के मोहल्ला रोड्डूपुर गली नजर सिंह वाली के गगनदीप सिंह उर्फ गगन के

रूप में हुई है। यह कार्रवाई पंजाब पुलिस की काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट और तरनतारन पुलिस ने की है। डीजीपी गौरव यादव के अनुसार, प्रारंभिक जांच में पता चला है कि गगनदीप सिंह 5 साल से पाकिस्तान में बैठे खालिस्तान समर्थक गोपाल सिंह चावला के संपर्क में था। चावला के जरिए ही उसका परिचय पाकिस्तानी खुफिया अधिकारियों से हुआ था।

वक्फ संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन के लिए पोर्टल लॉन्च करेगी सरकार

नई दिल्ली (एजेंसी)। केंद्र सरकार 6 जून को उम्मीद पोर्टल लॉन्च करने जा रही है। इसका मकसद वक्फ संपत्तियों के बेहतर प्रबंधन और पारदर्शिता को बढ़ावा देना है। उम्मीद का पूरा नाम है- यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट, एक्वायरमेंट, एफिशिएंसी और डेवलपमेंट। यह एक सेंट्रल पोर्टल होगा, जिस पर देशभर की वक्फ संपत्तियों को रजिस्टर किया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक, पोर्टल लॉन्च होने के छह महीने के भीतर सभी वक्फ संपत्तियों को रजिस्टर करना अनिवार्य होगा। इस पर संपत्तियों का पूरा विवरण देना होगा जैसे- लंबाई, चौड़ाई और जियो टैग की गई लोकेशन। अगर किसी संपत्ति का नाम किसी महिला के नाम पर दर्ज है, तो उसे वक्फ संपत्ति घोषित नहीं किया जा सकेगा। रजिस्ट्रेशन के लिए दो महीने का अतिरिक्त समय दिया जा सकता है रजिस्ट्रेशन का काम संबंधित राज्य वक्फ बोर्ड करेंगे। अगर किसी वजह से तकनीकी या अन्य कारणों से समय पर



रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया, तो 1 से 2 महीने की अतिरिक्त मोहलत दी जा सकती है। लेकिन अगर फिर भी संपत्ति रजिस्टर्ड नहीं होती, तो उसे विवादित मानते हुए वक्फ ट्रिब्यूनल के पास भेजा जाएगा। वक्फ संपत्तियों से मिलने वाले फायदों का अहम मकसद महिलाओं, बच्चों और कमजोर वर्गों को मदद देना रहेगा।

मुयमंन्त्री ने बाँबे ग्रीन और मणि प्रभा किस्म का स्वाद चख कर आम महोत्सव का किया शुभारंभ

भोपाल (एजेंसी)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मंगलवार को पंचमढ़ी के राज भवन परिसर में आम महोत्सव का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने मणि प्रभा एवं बाँम्बे ग्रीन किस्म के आम का स्वाद भी लिया। आम का रसास्वादन कर मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने आम की मिठास और स्वाद की सराहना की। उन्होंने प्रदर्शनी में लाए गए देशी आम भी चखे। प्रदर्शनी में जम्बो केसर, सुंदरजा, कृष्ण भोग, लंगड़ा आम, गजरिया, मालदा आदि किस्मों की सराहना की। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री श्री जगदीश देवड़ा एवं श्री

राजेंद्र शुक्ला के साथ-साथ लोक निर्माण मंत्री एवं नर्मदापुरम जिले के प्रभारी मंत्री श्री राकेश सिंह और और आम की विभिन्न किस्मों की सराहना की। इस अवसर पर नरसिंहपुर के किसान श्री विजय पाल सिंह ने आम की विभिन्न किस्मों की टोकरी मुख्यमंत्री डॉ. यादव को भेंट की। आम उत्पादक किसान श्री सुभाष पटेल ने मुख्यमंत्री डॉ यादव को यथार्थ गीता पुस्तिका भेंट की। मंगलवार को राजभवन पंचमढ़ी में आयोजित आम महोत्सव में जिन किस्मों का प्रदर्शन किया गया उनमें



आम्रपाली, लंगड़ा, दशहरी, चौसा, तोता परी, फ़ाज़ली, बंगाल पाली, तुरांपर, शुकर गुठली, मिश्री, हापुस, स्वर्णप्रभा, काला पहाड़, हिमसागर, स्वर्णरिखा, रत्ना, केसर, रुक्मणी, साबनिया, नीलम, सिंधु, जहांगीर, प्यारी, रॉयल मिस्त्री, जर्दालू, सेंसेशन,रस भंडार और राम केला शामिल है। मध्यप्रदेश के सुरुष्य पर्यटन स्थल पंचमढ़ी में दो दिवसीय आम महोत्सव का सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण, उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण मंत्री श्री नारायण सिंह कुशवाह ने भी जायजा लिया।

पाकिस्तान जाने से पहले- आने के बाद काशी गई यूट्यूबर ज्योति

वाराणसी (एजेंसी)। यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को एनआईए काशी लेकर आएगी। अभी तक की जांच में ज्योति के पाकिस्तान और काशी के बीच मूवमेंट का चौकाने वाला ट्रेंड सामने आया है। 2022 के बाद ज्योति 4 बार पाकिस्तान गई, लेकिन इस विजिट से पहले या बाद में वह काशी जरूर गई। ज्योति ने इसके वीडियो अपने चैनल ट्रैवल विद जो पर पोस्ट किए हैं। ज्योति काशी की विजिट बार-बार क्यों कर रही थी? क्या किसी के कहने पर चुनिंदा स्पॉट के वीडियो बनाकर पोस्ट किए गए?

राज्यपाल ने तमिलनाडु सरकार के बिलों को मंजूरी दी

चेन्नई (एजेंसी)। तमिलनाडु के राज्यपाल आरएन रवि ने सरकार की ओर से पारित 2 बिलों को मंजूरी दे दी है। इनसे 12,000 से ज्यादा दिव्यांगजनों को शहरी और स्थानीय निकायों में नामांकन का अधिकार मिलेगा। ये बिल लंबे समय से राजभवन में लंबित थे। राज्यपाल के इस फैसले पर मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने कहा- यह मंजूरी मिलनी ही थी। राज्यपाल को डर था कि अगर फिर से बिलों को रोका तो हम सुप्रीम कोर्ट



चले जाएंगे। 8 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु गवर्नर और राज्य सरकार के मामले पर राज्यपाल के अधिकार की सीमा तय कर दी थी। बेंच ने कहा था- राज्यपाल के पास

कोई वीटो पावर नहीं है। साथ ही सरकार के 10 जरूरी बिलों को राज्यपाल की ओर से रोके जाने को अवैध भी बताया था। कोर्ट ने कहा था कि यह मनमाना कदम है और कानून के नजरिए से सही नहीं है। राज्यपाल को राज्य की विधानसभा को मदद और सलाह देनी चाहिए थी। आदेश दिया कि विधानसभा से पास बिल पर राज्यपाल एक महीने के भीतर कदम उठाएं। सुप्रीम कोर्ट में तमिलनाडु सरकार की तरफ दायर याचिका पर सुनवाई हुई थी।

ऑपरेशन सिंदूर- विदेश गए डेलिगेशन से मिलेंगे प्रधानमंत्री मोदी

नई दिल्ली (एजेंसी)। ऑपरेशन सिंदूर और पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद के खिलाफ भारत का रुख दुनिया को बताने गए डेलिगेशन ग्रुप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले हफ्ते मुलाकात कर सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, पीएम मोदी सभी 7 डेलिगेशन ग्रुप से 9 या 10 जून को मिलेंगे। इस दौरान डेलिगेशन अपने दौरे की रिपोर्ट प्रधानमंत्री को देंगे। भाजपा के बैजयंत पांडा के नेतृत्व वाला डेलिगेशन आज मंगलवार को भारत लौट आया है। इस ग्रुप में भाजपा सांसद निशिकांत दुबे, फंगनन कोन्याक और रेखा शर्मा, सांसद असदुद्दीन ओवैसी, सतनाम

सिंह संधू, गुलाम नबी आजाद और पूर्व विदेश सचिव हर्ष श्रृंगला शामिल हैं। इन्होंने सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन और अल्जीरिया 4 देशों की यात्रा की। बाकी छह डेलिगेशन 8 जून तक विदेश दौरे से वापसी करेंगे। केंद्र सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर का मकसद दुनिया को बताने के लिए देश के 59 सांसदों को 33 देश भेजा। 59 सांसद को 7 सर्वदलीय टीमें (डेलिगेशन) में बांटा गया। 17 टीमों के साथ 8 पूर्व राजनयिक भी हैं। आतंकवाद पर ज़ीरो टॉलरेंस-इसमें बताएंगे कि ऑपरेशन सिंदूर आतंकी गुटों और उनके ढांचों के खिलाफ था।

कनिमोझी बोलीं- भारत की राष्ट्रीय भाषा है एकता और विविधता

मैड्रिड (एजेंसी)। भारत के ऑल पार्टी डेलिगेशन की अगुआई कर रहीं डीएमके सांसद कनिमोझी ने सोमवार को स्पेन में कहा कि भारत की राष्ट्रीय भाषा एकता और विविधता है। उन्होंने कहा कि यही संदेश यह प्रतिनिधिमंडल दुनिया को देने आया है। दरअसल, स्पेन में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए उनसे पूछा गया कि भारत की राष्ट्रीय भाषा

क्या है। इसके जवाब में कनिमोझी ने कहा, भारत की राष्ट्रीय भाषा है एकता और विविधता। यही सबसे जरूरी संदेश है जो आज दुनिया तक पहुंचाना चाहिए। कनिमोझी का यह बयान ऐसे समय में आया है जब हाल ही में डीएमके केंद्र सरकार की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शामिल तीन-भाषा फॉर्मूले का विरोध कर चुकी है। स्पेन में कनिमोझी के नेतृत्व में भारत का ग्रुप-6 डेलिगेशन स्पेन के विदेश मंत्री जोसे मैनुएल अल्बारेस से भी मिला।



5 विवादित इलाकों में बॉर्डर पिलर लगाएंगे असम-मेघालय

गुवाहाटी (एजेंसी)। असम और मेघालय के बीच लंबे समय से चल रहे सीमा विवाद को सुलझाने की दिशा में दोनों राज्यों ने एक अहम कदम उठाया है। दोनों राज्यों की सरकारों ने सोमवार को घोषणा की कि 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस तक पांच विवादित इलाकों में बॉर्डर पिलर लगाए जाएंगे। यह जानकारी दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने दी। ये पांच इलाके उन छह विवादित क्षेत्रों में शामिल हैं, जिनमें से कुल 12 विवादित क्षेत्रों को सुलझाने के लिए असम और मेघालय ने मार्च 2022 में एक समझौता किया था। गुवाहाटी में असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा और मेघालय के मुख्यमंत्री



कॉनराड संगमा ने एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। हिमंत बिस्व सरमा ने कहा, जिन छह क्षेत्रों को लेकर समझौता हुआ था, उनमें से पांच में 15 अगस्त तक बॉर्डर पिलर लगाने की कोशिश करेंगे।

पंजाब में सिंदूर पर सियासत तेज

चंडीगढ़ (एजेंसी)। पंजाब में ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर राजनीति गरमा गई है। सिंदूर घर-घर भेजने के मुद्दे पर सीएम भगवंत मान ने भाजपा पर तंज कसा है। उन्होंने कहा- क्या यह वन नेशन-वन हसबैंड स्कीम है? सिंदूर का मजाक उड़ाया जा रहा है। इससे पहले पंजाब कांग्रेस प्रधान अमरिंदर सिंह राजा वड्डिंग ने भी बीजेपी को घेरा था। उन्होंने कहा कि सिंदूर पर महिलाओं के पति

का हक है। उन्होंने पंजाब बीजेपी के नेताओं को सलाह दी कि घर-घर सिंदूर न भेजना, वरना पंजाबी महिलाएं उन्हें पीटेंगी। दरअसल, मंगलवार को सीएम भगवंत मान कैबिनेट मीटिंग के बाद मीडिया के सवालों के जवाब दे रहे थे। इस दौरान उनसे पूछा गया कि बीजेपी नेता सिंदूर के नाम पर वोट मांग रहे हैं। इस पर सीएम ने कहा कि यह बहुत ही दुखदायी है।

अहमदाबाद में 24 घंटे में कोरोना के 60 केस

नई दिल्ली (एजेंसी)। देश में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। गुजरात के अहमदाबाद में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 60 केस मिले हैं। राजकोट में स्क्व हिमकर सिंह भी कोरोना पॉजिटिव हैं। वे फिलहाल होम आइसोलेशन में हैं। देशभर में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना से 5 लोगों की मौत भी हुई है। इनमें केरल, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में एक-एक और महाराष्ट्र में दो मौतें हुई हैं। जनवरी से अब तक देश में कोरोना से 38 मौतें हो चुकी हैं। इनमें से 31 की मौत बीते 4 दिन में हुई हैं। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 10 मौतें हुई हैं। भारत में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 4 हजार के पार हो गया है। अभी देश में कुल 4,026 एक्टिव केस हैं। इनमें 50ब केस सिर्फ महाराष्ट्र और केरल में हैं। केरल में सबसे ज्यादा 1,446 एक्टिव केस हैं। इसके बाद महाराष्ट्र में 494, गुजरात में 397



और दिल्ली में 393 मामले हैं। देश में 22 मई से कोरोना के मामले लगभग

15 गुना बढ़े हैं। 22 मई को देश में सिर्फ 257 एक्टिव मामले थे। 31 मई

तक यह आंकड़ा बढ़कर 3,395 हो गया था। उसके बाद से केस लगातार बढ़ रहे हैं। 2700 मरीज ठीक भी हुए हैं। हाईकोर्ट ने कहा- कोविड की अगली महामारी अभी खत्म नहीं हुई दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को कहा- कोविड की अगली महामारी अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि यह अभी भी एक्टिव है। कोर्ट ने केंद्र सरकार से सेंट्रल कलेक्शन सेंटर और ट्रांसपोर्ट पॉलिसी को लेकर की गई तैयारियों की जानकारी मांगी है। कोर्ट ने कहा कि 30 मई 2023 को हुई बैठक के बाद जो भी निर्णय लिए गए, उन्हें लागू करने में अगर कोई खालीपन है तो यह गंभीर मामला है। जस्टिस निरीश कथपालिया ने कहा कि यह मानकर चलना चाहिए कि जरूरी कदम और प्रोटोकॉल तय किए जा चुके होंगे, लेकिन संबंधित अधिकारियों को इसे रिकॉर्ड पर लाना चाहिए।

आदिल राशिद बने इंग्लैंड के नंबर एक स्पिनर

नई दिल्ली (एजेंसी)। इंग्लैंड के लेग स्पिनर आदिल राशिद अब अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में इंग्लैंड की ओर से सबसे अधिक विकेट लेने वाले स्पिनर बन गये हैं। आदिल ने दिग्गज स्पिनर ग्रीम स्वान को पीछे छोड़ दिया है और वह नंबर एक स्थान पर आ गये हैं। राशिद ने 298 पारियों में 412 विकेट लिए हैं जबकि स्वान ने 223 पारियों में 410 विकेट लिए थे। राशिद को लंबे समय तक बेहतर प्रदर्शन के कारण ही यहां तक पहुंचे हैं। अच्छी लेंग स्पिन और विविधतापूर्ण गेंदबाजी के कारण ही वह सीमित ओवरों के प्रारूप में इंग्लैंड के प्रमुख खिलाड़ी बने हैं। एकदिवसीय और टी20

क्रिकेट में उनकी गूगली और फिलपर को खेलना बल्लेबाजों के लिए बेहद कठिन रहा है। इससे आधुनिक क्रिकेट में स्पिन गेंदबाजी का दबदबा भी बढ़ा है। राशिद ने स्वान की तुलना में अधिक पारियां खेलीं पर निरंतरता और हालात के अनुसार ढलने से ही वह यहां तक पहुंचे हैं।

उन्होंने अपने प्रदर्शन से युवा स्पिनरों के लिए एक नया मानदंड स्थापित किया है। वहीं सबसे अधिक विकेट लेने के मामले में तीसरे स्थान पर मोईन अली हैं, उन्होंने 318 पारियों में 366 विकेट लिए हैं। अली की ऑफ स्पिन और ऑलराउंड क्षमता से भी इंग्लैंड को कई अवसरों पर लाभ हुआ है।

14 जून से होगा 2025 क्लब वर्ल्ड कप फुटबॉल टूर्नामेंट

नई दिल्ली (एजेंसी)। 2025 क्लब वर्ल्ड कप फुटबॉल टूर्नामेंट इसी माह 14 जून से 13 जुलाई, 2025 तक संयुक्त राज्य अमेरिका में होगा। इस टूर्नामेंट में कुल 32 टीमों भाग लेंगी। इसमें सात मैचों का ग्रुप स्टेज और प्लेऑफ फॉर्मेट होगा। विश्व फुटबॉल की शीर्ष संस्था फीफा ने इसके लिए इनामी राशि घोषित कर दी है।

इसमें कुल इनामी राशि 1 बिलियन डॉलर 32 प्रतिभागी क्लबों में वितरित की जाएगी। इसमें विजेता टीम को 125 मिलियन डॉलर तक जीतने का निर्धारित।अवसर मिलेगा। इसके अलावा वैश्विक क्लब फुटबॉल को समर्थन देने के लिए 250 मिलियन डॉलर अलग रखे गए हैं। वहीं इसमें शामिल टीमों को 525 मिलियन

डॉलर मिलेंगे। इसके अलावा यूईएफए क्लब 12.81 मिलियन डॉलर से 38.19 मिलियन डॉलर तक की राशि हासिल करेंगे, जो उनकी रैंकिंग और राजस्व पर निर्भर करेगा। इसके तहत शीर्ष स्तर के क्लब चेल्सी, मैनचेस्टर सिटी, रियल मैड्रिड और बार्सेलोनानाई इनामी राशि हासिल करने की दावेदार रहेंगी। कॉम्मेबोल (दक्षिण अमेरिकी) क्लब को 15.21 मिलियन डॉलर के करीब रकम मिलेगी। कॉन्कैकएफ, सीएफए और एएफसी क्लब को 9.55 मिलियन डॉलर मिलेंगे जबकि ओएफसी (ओशिनिया) क्लब 3.58 मिलियन डॉलर दिये जाएंगे। टूर्नामेंट से होने वाली सभी कमाई क्लब फुटबॉल के विकास में ही लगाई जाएगी।

भारत के खिलाफ खासे सफल रहे हैं स्मिथ

नई दिल्ली (एजेंसी)। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान स्टीव स्मिथ भारतीय गेंदबाजों के लिए हमेशा ही परेशानी साबित हुए हैं। स्मिथ का रिकार्ड भारतीय टीम के खिलाफ काफी अच्छा रहा है। 2015 एकदिवसीय विश्वकप की बात करें या 2023 विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप के सेमीफाइनल सहित कई मैचों में स्मिथ के कारण ही भारतीय टीम जीत हासिल नहीं कर पायी। डब्ल्यूटीसी फाइनल 2023 में स्मिथ ने 121 रन बनाए थे। इस मैच में उनकी और ट्रेविस हेड के बीच हुई 285 रनों की साझेदारी से ये मैच

ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया था। भारतीय टीम के खिलाफ स्मिथ ने 24 टेस्ट मैचों में 58.90 के औसत से 2356 रन बनाए हैं। इस दौरान उन्होंने 11 शतक और 5 अर्धशतक लगाये हैं। वहीं एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय में भी स्मिथ का औसत भारत के खिलाफ 50 से अधिक का रहा है। भारतीय टीम के खिलाफ 30 एकदिवसीय मैचों में स्मिथ ने 53.19 की औसत से 1383 रन बनाए, जिसमें 5 शतक और 7 अर्धशतक शामिल हैं। वहीं टी20 अंतरराष्ट्रीय में स्मिथ ने भारतीय टीम के खिलाफ 11 मैचों में 229 रन बनाये हैं।

आईएसएसएफ निशानेबाज विश्व कप आठ जून से

नई दिल्ली (एजेंसी)। ओलंपिक पदक विजेता निशानेबाज मनु भाकर और स्वप्निल कुसाले अगले माह आठ जून से शुरू होने वाले अ। ई। एस। एस। एफ राइफल/पिस्टल विश्व कप के म्यूनख चरण में भारत की ओर से पदक के प्रबल दावेदार रहेंगे।

भाकर और कुसाले को 23 सदस्यीय भारतीय टीम में शामिल किया गया है। भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ (एनआरआई) ने भाकर को दो व्यक्तिगत स्पर्धाओं (महिलाओं की 10 मीटर और 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा) में शामिल किया है। वहीं पुरुष एयर राइफल में संदीप सिंह को भी जगह मिली है। कुसाले और संदीप पेरिस खेलों में भाग लेने के बाद पहली बार किसी स्पर्धा में खेलते दिखेंगे। भारतीय राइफल और पिस्टल टीम ने



हाल ही में अर्जेंटीना और पेरू में आयोजित दो-चरण वाले संयुक्त आईएसएसएफ विश्व कप में बेहत प्रदर्शन किया था

इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट टीम में जगह नहीं मिलने से श्रेयस अय्यर हुए थे दुखी, कोच रिकी पोंटिंग ने किया खुलासा

नई दिल्ली (एजेंसी)। पंजाब किंग्स ने दूसरे क्कालीफायर में मुंबई इंडियंस को पांच विकेट से हराकर फाइनल में प्रवेश कर लिया। पंजाब किंग्स के इस बेहतरीन जीत के बाद ये भी तय हो गया कि आईपीएल को इस सीजन में एक नया चैंपियन मिलेगा। वहीं अब 3 जून को फाइनल में पंजाब का सामना आरसीबी से होगा और दोनों टीमों ने 18 साल में एक बार भी खिताब नहीं जीता है। पंजाब किंग्स ने 11 साल बाद फाइनल में जगह बनाई है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पोंटिंग का मानना है कि श्रेयस अय्यर का हालिया शानदार प्रदर्शन टेस्ट टीम में जगह ना मिलने से प्रेरित है।

श्रेयस अय्यर ने ने मुंबई इंडियंस के खिलाफ नाबाद 87 रनों की बेहतरीन पारी खेली। पंजाब किंग्स के कोच रिकी पोंटिंग ने भारतीय टेस्ट टीम में श्रेयस अय्यर को जगह नहीं मिलने पर हैरानी जताई है। उनके जैसा प्रदर्शन करने वाले अन्य खिलाड़ियों को मौका मिला है। उन्होंने कहा कि, मैं वास्तव में दुखी था। लेकिन उसने अच्छे से इसे स्वीकार किया



30 सितंबर से खेला जाएगा महिला टी20 विश्वकप-आईसीसी



दुबई। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) ने कहा है कि महिला टी20 विश्व कप 30 सितंबर से दो नवंबर के बीच भारत और श्रीलंका में खेला जाएगा। आईसीसी के अनुसार इसमें कोलंबो को अतिरिक्त तटस्थ स्थल के रूप में जोड़ा

गया है। भारत पहले अकेले ही इसकी मेजबानी करने जा रहा था पर अब इसके मैच बेंगलुरु, गुवाहाटी, इंदौर, विशाखापत्तनम के अलावा कोलंबो में भी खेले जाएंगे। कोलंबो को इसलिए शामिल किया गया है ताकि यहां पाकिस्तान के

मुकाबले हो सकें। इस साल की शुरुआत में ही चैम्पियंस ट्रॉफी के दौरान आईसीसी ने हाइब्रिड मॉडल को मंजूरी दी गई थी। जिसके तहत भारतीय टीम ने अपने मैच दुबई में खेले थे जबकि अन्य टीमों के मैच पाकिस्तान में हुए थे। आईसीसी ने कहा कि यह टूर्नामेंट बेंगलुरु में 30 सितंबर से शुरू होगा।

गौरतलब है कि भारत में 12 साल बाद महिला क्रिकेट विश्व कप कराया जा रहा है। पहला सेमीफाइनल 29 अक्टूबर को गुवाहाटी या कोलंबो में खेला जाएगा जबकि दूसरा 30 अक्टूबर को बेंगलुरु में होगा। वहीं फाइनल दो नवंबर को बेंगलुरु या कोलंबो में खेला जाएगा। इस टूर्नामेंट में मेजबान भारतीय टीम के अलावा गत चैम्पियन ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंग्लैंड, श्रीलंका, न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका की टीमों इसमें भाग लेंगी।

सचिन,धोनी की तरह विराट की जर्सी भी होगी रिटायर !

नई दिल्ली (एजेंसी)। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और अनुभवी बल्लेबाज विराट कोहली को सम्मानित करने भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) उनकी जर्सी नंबर 18 को रिटायर कर सकती है। इससे भारतीय टेस्ट टीम में आने वाले समय में किसी भी खिलाड़ी को ये जर्सी नंबर नहीं मिलेगा। जर्सी नंबर 18 नंबर कीपिछले 14 साल से विराट के पास रही है। कोहली ने अभी एकदिवसीय से संन्यास नहीं लिया है ऐसे में वह फिलहाल इस जर्सी में खेलते हुए देखेंगे पर यह माना जा रहा है कि जिस

प्रकार सचिन तेंदुलकर (जर्सी नंबर 10) और महेंद्र सिंह धोनी (जर्सी नंबर 7) की जर्सी किसी अन्य खिलाड़ी को नहीं मिली। उसी प्रकार किसी भी नये खिलाड़ी को 18 नंबर की जर्सी नहीं मिलेगी।

वहीं युवा तेज गेंदबाज मुकेश कुमार के इंडिया ए की ओर से 18 नंबर की जर्सी पहनने को लेकर भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) के एक सीनियर अधिकारी का कहना है कि मुकेश कुमार ने इंग्लैंड लार्थस के खिलाफ पहले 'टेस्ट मैच में 18 नंबर की जर्सी पहनी जरूर थी पर इससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि भारत

ए टीम में कोई निश्चित नंबर के साथ ही जर्सी पर नाम नहीं होता है।कोई भी खिलाड़ी कोई भी नंबर चुन सकता है। जर्सी नंबर केवल अंतरराष्ट्रीय मैचों के लिए ही मान्य है। भारतीय टेस्ट टीम में दो नए सदस्य बी साई सुदर्शन और अर्शदीप सिंह शामिल हुए हैं लेकिन उन्हें जो जर्सी नंबर दिए गए हैं, वे अलग हैं। भारतीय टीम में किसी विशेष जर्सी नंबर को आधिकारिक रूप से 'रिटायर करने प्रथा नहीं है लेकिन कुछ मशहूर नंबर बाद में टीम में शामिल हुए खिलाड़ियों ने नहीं पहने हैं।

साउथ अफ्रीकी बल्लेबाज हेनरिक क्लासेनने लिया संन्यास



नई दिल्ली (एजेंसी)। क्रिकेट जगत में संन्यास लेने का दौर जारी है। लगातार एक के बाद एक करके कई दिग्गज क्रिकेटर संन्यास का ऐलान कर रहे हैं। वहीं सोमवार, 2 जून को पहले ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल ने वनडे क्रिकेट को अलविदा कह दिया। वहीं अब साउथ अफ्रीका के धाकड़ बल्लेबाज हेनरिक क्लासेन ने क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट को अलविदा कह दिया। इसकी जानकारी उन्होंने खुद सोशल मीडिया के जरिए दी।

हेनरिक क्लासेन ने इंस्टाग्राम पर लिखा कि, ये मेरे लिए दुःखद दिन है क्योंकि मैंने अंतराष्ट्रीय क्रिकेट से दूर रहने का फैसला किया है। मुझे ये फैसला करने में काफी समय लगा कि मेरे और मेरे परिवार के भविष्य के लिए क्या बेहतर है।

उन्होंने आगे लिखा कि, पहले दिन से ही अपने देश का प्रतिनिधित्व करना मेरे लिए सबसे बड़ा सम्मान था और ये वह सब कुछथा जिसके लिए मैंने एक युवा लड़के के रूप में काम किया था और जिसका सपना देखा था। मैं अपने परिवार के साथ ज्यादा समय बिताने के लिए उत्सुक हूँ क्योंकि ये फैसला मुझे ऐसा करने की अनुमति देगा। बता दें कि, पिछले साल जनवरी में 32 वर्षीय क्लासेन ने सफेद गेंद वाले क्रिकेट पर ध्यान केंद्रित करने के लिए टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की थी। हेनरिक क्लासेन ने साउथ अफ्रीका के लिए पिछले साल आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ आखिरी मैच खेला था। फिलहाल, क्लासेन ने साउथ अफ्रीका के लिए 4 टेस्ट में 104 रन, 60 वनडे में 2141 रन और 58 टी20 मैचों में 1000 रन बनाए।

पीठ की सर्जरी के लिए न्यूजीलैंड जाएंगे मयंक यादव

नई दिल्ली (एजेंसी)। पिछले काफी समय से पीठ की समस्या से जूझ रहे युवा तेज गेंदबाज मयंक यादव अब सर्जरी के लिए न्यूजीलैंड जाएंगे। होगी। मयंक उसी डॉक्टर से अपनी सर्जरी कराएंगे जिसने जसप्रीत बुमराह की सर्जरी की थी। यह सर्जरी न्यूजीलैंड के क्राइस्टचर्च में स्थित प्रसिद्ध ऑर्थोपेडिक स्पाइन सर्जन डॉ. रोबन शाउटेन करेंगे। डॉ. शाउटेन ने ही साल 2023 में जसप्रीत बुमराह और प्रसिद्ध कृष्णा की सर्जरी की थी, साथ ही ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाजों जेसन बेहरेनडॉर्फ और जेम्स पैटिनसन का भी इलाज किया था। पिछले साल, शाउटेन और ग्राहम इंगलिस ने स्ट्रेस फ्रैक्चर से परेशान ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर कैमरन ग्रीन की पीठ की सर्जरी भी की थी।

माना जा रहा है कि मयंक बार-बार हो रही पीठ की समस्या को पूरी तरह से ठीक करने अब सर्जरी कराना चाहते



हैं। ऐसे में बुमराह ने जिस प्रक्रिया से गुजरे थे, वही प्रक्रिया मयंक के लिए भी अपनाई जाएगी। माना जा रहा है कि यह कदम मयंक के लिए

फायदेमंद है, क्योंकि यह उनकी तेज गेंदबाज के रूप में लंबी उम्र को बढ़ाएगा। मयंक को इस बारे में बता दिया गया है और वह कुछ दिनों में

न्यूजीलैंड रवाना होंगे। सर्जरी के बाद, वह 22 से 25 दिनों तक वहां रहेंगे ताकि रिहैबिलिटेशन और रिकवरी प्रक्रिया को सही से पूरा किया जा सके।

गौरतलब है कि मयंक ने अक्टूबर 2024 में बांग्लादेश के खिलाफ तीन टी20 मैचों में भारत के लिए डेब्यू किया था पर चोट के कारण वह पूरे समय नहीं खेल पाये थे। 2024/25 के घरेलू सीजन में भी वह पीठ की समस्या के कारण बाहर रहे। आईपीएल में लखनऊ सुपर जायंट्स (एलएसजी) ने उन्हें आईपीएल 2025 के लिए रिटेन किया पर पैर की उंगली में चोट के कारण वह ढेर से टीम में शामिल हुए। मयंक ने आईपीएल 2025 में केवल दो मैच खेले, जहां उनकी गति घटकर 130 किमी/घंटा तक सीमित रही। इसके बाद मयंक की पीठ की चोट फिर उभरी, जिसके कारण वह पूरी तरह से टूर्नामेंट से बाहर हो गए।

जनसुनवाई में 86 आवेदकों की सुनीं गई समस्यायें



मीडिया ऑडीटर, रीवा (निप्र)। कलेक्ट्रेट कार्यालय में प्रति सप्ताह आयोजित होने वाली जनसुनवाई में अपर कलेक्टर श्रीमती सपना त्रिपाठी ने 86 आवेदकों की समस्यायें सुनीं तथा संबंधित आवेदनों को विभागीय अधिकारियों को प्रेषित कर आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिये। संयुक्त कलेक्टर पी.के. पाण्डेय ने भी जनसुनवाई की।

जनसुनवाई में तिघरा निवासी बालमीक शुक्ला के सीमांकन कराने, बरा 396 के रामगोपाल मिश्रा के खसरा सुधार कराने, लौवा निवासी नंदकिशोर कुशवाहा के पुनः सीमांकन कराने तथा रौरा निवासी महेन्द्र कुमार के नामांतरण कारक कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया। इसी प्रकार पाती निवासी रामनिवास यादव ने सड़क दुर्घटना में मृत पत्नी के आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत करने के आवेदन को तहसीलदार हुजूर को कार्यवाही करने हेतु प्रेषित किया गया। गणेश प्रसाद विश्वकर्मा निवासी अमवा के भूमि अतिक्रमण मुक्ति कराने के आवेदन को

एसडीएम मनगवां को, गहिलवार निवासी प्रदीप कुमार मिश्रा के नक्शा संशोधन के आवेदन को नायब तहसीलदार डभौरा को तथा बीड़ा निवासी श्रीमती रामदुलारी के अवरूद्ध रास्ता को खुलवाने के आवेदन को तहसीलदार सेमरिया को कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया। जनसुनवाई में महमूदपुर के जगदीश प्रसाद मिश्रा तथा भेलौड़ी निवासी नागेन्द्र शुक्ला के भूमि अधिग्रहण का मुआवजा दिलाने के आवेदनों को सिंचाई विभाग को तथा नदना निवासी शंकर प्रसाद पाण्डेय के खाद्यान्न दिलाने के आवेदन पर खाद्य अधिकारी को कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये। इसी क्रम में शांति देवी सेमरिया निवासी के परिवार पेंशन प्रदाय करने के आवेदन पर पेंशन अधिकारी को तथा छोटेलाल तिवारी निवासी छत्रपति नगर के नाली निर्माण के आवेदन को आयुक्त नगर निगम को प्रेषित किया गया। पुष्पराज पटेल एवं ग्रामवासी कुंड्या के स्थगन के बाद भी निर्माण कार्य पर रोक लगाने के आवेदकों सीईओ जिला पंचायत को कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया।

कमिश्नर ने विभागीय कार्यों तथा सीएम हेल्पलाइन प्रकरणों के निराकरण की समीक्षा की

विकसित कृषि संकल्प अभियान से हर किसान को जोड़ें, जल संरक्षण के कार्यों में भागीदारी निभाएं



मीडिया ऑडीटर, रीवा (निप्र)। कमिश्नर कार्यालय सभागार में आयोजित बैठक में कमिश्नर बीएस जामोद ने विभागीय कार्यों तथा सीएम हेल्पलाइन प्रकरणों के निराकरण की समीक्षा की। कमिश्नर ने कहा कि विकसित कृषि संकल्प अभियान में सभी जिलों में तीन-तीन दल ग्राम पंचायतों का भ्रमण करके किसानों को खेती की आधुनिक तकनीक से परिचित करा रहे हैं। मैदानी कर्मचारियों तथा ग्राम पंचायत के सहयोग से विकसित कृषि संकल्प अभियान से हर किसान को जोड़ें। कृषि विशेषज्ञ किसान के पास स्वयं पहुंचकर खेती की आधुनिक तकनीक और कृषि, पशुपालन, मछलीपालन तथा उद्यानिकी विभाग की योजनाओं की जानकारी दे रहे हैं। अधिक से अधिक किसान इसका लाभ उठा सके इसके लिए समन्वित प्रयास करें। अभियान के तहत विभिन्न विभागों द्वारा पात्र किसानों

का मौके पर ही आवेदन लेकर विभिन्न योजनाओं के लिए पंजीयन भी किया जा रहा है। बैठक में कमिश्नर ने कहा कि जल गंगा संवर्धन अभियान भावी पीढ़ी को सुरक्षित रखने का अभियान है। शासन के इस महत्वपूर्ण अभियान में हर अधिकारी भागीदारी निभाकर योगदान दे। संभागीय दल में शामिल सभी अधिकारी सप्ताह में दो दिन क्षेत्र का भ्रमण करके जल गंगा संवर्धन अभियान की मानीटरिंग करें और जल संरक्षण कार्य में श्रमदान करें। भ्रमण के दौरान अन्य विभागों की योजनाओं अथवा जन समस्याओं से जुड़ी महत्वपूर्ण सूचना मिलने पर तत्काल अवगत कराएं। बैठक में कमिश्नर ने कहा कि समर्थन मूल्य पर गेहूँ उपार्जन के बाद अभी चार प्रतिशत गेहूँ का संभाग में परिवहन शेष है। इसका दो दिवस में सुरक्षित भण्डारण कराकर शेष किसानों को लंबित राशि का भुगतान

कराएं। शासन द्वारा उचित मूल्य की दुकानों से वितरण के लिए तीन माह का खाद्यान्न एक साथ आवंटित किया गया है। क्षेत्रीय प्रबंधक नागरिक आपूर्ति निगम आवंटित खाद्यान्न का एक सप्ताह में उठाव करके दुकानों में भण्डारण कराएं। खाद्यान्न वितरण के समय शेष बचे हितग्राहियों की ई केवाईसी अपडेशन भी अनिवार्य रूप से कराएं। शासन ने इसके लिए समय सीमा को 15 जून तक बढ़ा दिया है। कमिश्नर ने कहा कि 31 मई तक सेवानिवृत्त हुए 52 शासकीय सेवकों के पेंशन प्रकरण अभी लंबित हैं। संबंधित अधिकारी 7 दिवस में पेंशन प्रकरण अनिवार्य रूप से पेंशन कार्यालय में दर्ज कराएं। शिक्षा, गृह, ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य, उच्च शिक्षा तथा राजस्व विभाग पेंशन प्रकरणों के निराकरण पर विशेष ध्यान दें। सभी अधिकारी सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों का

तत्परता से निराकरण करें। पीएचई, गृह, स्वास्थ्य ऊर्जा, राजस्व तथा श्रम विभाग में लंबित प्रकरणों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है। बैठक में कमिश्नर ने महाप्रबंधक उद्योग को स्वरोजगार के प्रकरणों तथा औद्योगिक विकास केन्द्रों की गतिविधियों के विवरण देने के निर्देश दिए। बैठक में संयुक्त आयुक्त दिव्या त्रिपाठी, उपायुक्त राजस्व श्रेयस गोखले, डीन मेडिकल कालेज डॉ सुनील अग्रवाल, अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा आरपी सिंह, क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य डॉ एमएल गुप्ता, संयुक्त संचालक महिला एवं बाल विकास ऊषा सिंह सोलंकी, सहायक संचालक कृषि प्रीति द्विवेदी, संयुक्त संचालक पशुपालन डॉ राजेश मिश्रा, संयुक्त संचालक पेंशन एमएस पैकरा तथा अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

जिले के प्रभारी मंत्री आज आएंगे, महिला स्वसहायता समूह सम्मेलन में होंगे शामिल

मीडिया ऑडीटर, रीवा (निप्र)। पंचायत एवं ग्रामीण विकास तथा श्रम मंत्री और रीवा जिले के प्रभारी मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल 4 जून को रीवा आएंगे। प्रभारी मंत्री श्री पटेल उमरिया से मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के साथ दोपहर 3 बजे हेलीकाप्टर द्वारा प्रस्थान कर दोपहर 3.45 बजे गंगेव हेलीपैड पहुंचेंगे और मनगवां विधानसभा क्षेत्र गंगेव स्टेडियम में आयोजित महिला स्वसहायता समूह सशक्तिकरण सम्मेलन में मुख्यमंत्री जी के साथ शामिल होंगे। कार्यक्रम के बाद मंत्री श्री पटेल मुख्यमंत्री डॉ यादव के साथ शाम 5.45 बजे मनगवां से प्रस्थान कर शाम 6 बजे रीवा आएंगे और शाम 6.10 बजे भोपाल के लिए प्रस्थान करेंगे।

धान की रोपाई के लिए सबसे सफल है आटोमेटिक धान रोपाई यंत्र

मीडिया ऑडीटर, रीवा (निप्र)। रीवा संभाग के रीवा और सतना जिलों में धान का विपुल उत्पादन होता है। संभाग के अन्य जिलों में भी धान की बड़े पैमाने पर खेती की जाती है। धान की खेती के लिए किसान मुख्य रूप से रोपाई का उपयोग किया जा रहा है। छिटवा धान की खेती का क्षेत्र बहुत कम हो गया है। धान की रोपाई के लिए बड़ी संख्या में कुशल और परिश्रमी मजदूरों की आवश्यकता होती है। धान का रोपा तैयार करने के बाद उसे 21 दिन में नर्सरी से निकालकर खेत में रोपाई करना आवश्यक होता है। सभी किसानों को लगभग एक समय ही बड़ी संख्या में मजदूरों की आवश्यकता होने से पर्याप्त मजदूर मिलना कठिन हो जाता है। रोपाई में देरी से भी धान के उत्पादन में गिरावट आती है। इस समस्या का कारगर समाधान आटोमेटिक धान रोपाई यंत्र है। इसे ट्रैक्टर से जोड़कर आसान से चलाया जा सकता है। इससे रोपाई करने पर कतार से कतार और पौधे से पौधे की दूरी तय रहती है। कतार से पौधे रोपित होने पर कोनाबीडर अथवा अन्य उपकरणों के उपयोग से फसल से खरपतवार निकालने में सहूलियत होती है। आटोमेटिक धान रोपाई यंत्र से एक साथ आठ कतारों में पौधों का रोपण होता है। रोपाई के लिए धान के पौधे चटाईनुमा तकनीक से तैयार किए जाते हैं। एक हेक्टेयर में रोपाई के लिए 100 वर्गमीटर की नर्सरी आवश्यक होती है। नर्सरी में गोबर की खाद तथा भुरभुरी मिट्टी में धान के पौधे तैयार किए जाते हैं। रोपाई के लिए इन्हें निश्चित मात्रा में रोपाई यंत्र की प्लेट पर रखा जाता है। इससे धान की रोपाई करने पर परिश्रम, लागत और समय की लगभग 50 प्रतिशत बचत होती है। साथ ही धान के उत्पादन में 30 से 40 प्रतिशत की वृद्धि होती है। धान रोपाई यानी पैडी ट्रांसप्लान्ट विभिन्न मॉडलों में उपलब्ध है। इसे खरीदने पर भी किसान को पात्रता के अनुसार अनुदान राशि का लाभ दिया जाता है।

भूमि अर्जन और पुनर्वासन संबंधी जनसुनवाई 5 को

मीडिया ऑडीटर, रीवा (निप्र)। अनुविभागीय अधिकारी राजस्व अनुभाग हुजूर कार्यालय में 5 जून को सुबह 10 बजे से सार्वजनिक जनसुनवाई का आयोजन किया गया है। यह जनसुनवाई तहसील हुजूर में टेकहा तिराहे पर जवशन इम्पूवमेंट एवं सड़क निर्माण के लिए भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (2013 का 30) की धारा-5 के तहत की जा रही है। एसडीएम हुजूर वैशाली जैन ने क्षेत्र के हितबद्ध व्यक्तियों से सार्वजनिक जनसुनवाई में निधारित स्थान व समय में उपस्थित होने की अपेक्षा की है।



सबके साथ आगे बढ़ता

जनजातीय समाज





नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री



डॉ. मोहन यादव, मुख्यमंत्री

राज्य स्तरीय

पेसा महासम्मेलन

मुख्य अतिथि

डॉ. मोहन यादव

मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश

4 जून 2025 | अपराह्न 1:00 बजे

D11037/25 पाली ब्लॉक, जिला उमरिया

पेसा अधिनियम के माध्यम से पूर्ण हो रहा है पंचायती राज संस्थाओं एवं आदिवासी क्षेत्रों की ग्राम सभाओं के सशक्तिकरण का उद्देश्य

- गांव की जमीन और वन क्षेत्र के दस्तावेज बिना तहसील कार्यालय जाये सीधे पटवारी और बीटगार्ड से हो रहे हैं प्राप्त
- भू-अर्जन, खनिज सर्वे, पट्टा और नीलामी हेतु अनिवार्य है ग्राम सभा की सहमति और अनुशंसा
- लघु वनोपज एवं तेंदूपत्ता के संग्रहण और विपणन का अधिकार मिलने से अब जनजातीय समुदाय स्वयं तय करता है अपनी लघु वनोपज का मूल्य
- जलाशयों में मछली पालन एवं सिंघाड़ा उत्पादन का अधिकार मिलने से आमदनी में हो रही है वृद्धि
- सार्वजनिक स्थानों पर शराब को प्रतिबंधित करने एवं अवैध बिक्री रोकने का अधिकार अब ग्राम सभा के पास
- गलत तरीके से आदिवासियों की जमीन खरीदने या कब्जा करने पर ग्राम सभा का हस्तक्षेप। नहीं हो सकता अब उनके साथ छल-कपट





आकल्पन : म.प्र. माध्यम/2025

सीधा प्रसारण

webcast.gov.in/mp/cmevents

@Cmmadhyapradesh @jansampark.madhyapradesh

@Cmmadhyapradesh @jansamparkMP

JansamparkMP

मध्यप्रदेश जनसम्यक् द्वारा जारी

स्वत्वाधिकारी मुद्रक/प्रकाशक संदीप द्विवेदी द्वारा मीडिया ऑडीटर पब्लिकेशन प्रा.लिमि. राजीव मार्ग निराला नगर रीवा से मुद्रित कर मीडिया ऑडीटर कार्यालय राजीव मार्ग निराला नगर रीवा से प्रकाशित, संपादक संदीप द्विवेदी, आर.एन.आई नं. 69082/97, डाक पंजीयन क्र.- म. प्र./ रीवा संभाग/ 46/2023-2025, प्रधान कार्यालय रीवा (सिटी कार्यालय चक्रपर सिटी सेंटर रीवा) फोन. नं. 9589645803, 7974467831 Mediaauditor1@gmail.com सभी विवादों का न्याय क्षेत्र रीवा होगा।